बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मकड़जाल

Rajiv Dixit

WWW.RAJIVDIXITMP3.COM

(09928064941, 09782705883

आमुख

मानव समाज के लम्बे इतिहास में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उदय एक ऐसी घटना है जिसने मनुष्य की जीवन शैली और अनुभव से परखे टिकाऊ मूल्यों को झकझोर दिया है। नवजात शिशु के भरपूर पोषण के लिए प्रकृति प्रदत्त माँ के स्तनपान की चिरकाल से चली आयी स्वास्थ्य परम्परा के स्थान पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 'बेबी फूड' को स्थापित करवा देना इसका एक उदाहरण मात्र है। राज्य, राष्ट्रीयता, धर्म, ईमान इन सब से ऊपर उठकर मुनाफा और आर्थिक साम्राज्य की हवस ने इन कम्पनियों को 'सुपरस्टेट' बना डाला है जो प्रकृति और मनुष्य दोनों के शोषण पर टिकी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में – रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान से लेकर युद्ध के विकराल हथियार बनाने तक – इनकी घुसपैठ है। विश्व के पर्यावरण को, विभिन्न क्षेत्रों में उद्‌भूत संस्कृतियों को इन ण्बवउकम्पनियों ने रोड रोलर की तरह रौंद डाला है।

यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति ने पश्चिम के देशों को अपने उपनिवेश बनाने में बड़ी मदद दी। इस उपनिवेशीकरण ने पश्चिम के देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को तीसरी दुनिया के देशों में अपना व्यापार जाल फैलाने का भरपूर अवसर दिया। उपनिवेशी ताकतों की छत्र छाया में इन्होंने लातीनी अमरीका, अफ्रीका और एशिया के देशों से सस्ता कच्चा काल बटोरा और अपने महंगे 'बने बनाए' माल से उनके बाजारों को पाट दिया। नतीजतन इन देशों की टिकाऊ अर्थव्यवस्था टूट गयी और सम्पन्न देश अविकसित देशों की श्रेणी में धकेले दिये गये। द्वितीय महायुद्ध के बाद उपनिवेशीकरण का जाल टूटा, पर विकास के नाम पर ये कम्पनियाँ तीसरी दुनिया में अपनी घुसपैठ बनाए रहीं। उपनिवेशकाल में जो काम पुलिस–फौज के हथियार करते थे, उत्तर उपनिवेशकाल में वह काम विश्व बैंक और मुद्राकोष की सहायता से ऋण के हथियार द्वारा किया गया। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को तीसरी दुनिया में निर्बाध रूप से अपने पाँव पसारने का कानूनी हक गैट के यूरूग्वे चक्र की समाप्ति पर बने विश्व व्यापार संगठन ने दे दिया जिसके तहत ये कम्पनियाँ इन देशों से 'राष्ट्रीय व्यवहार' पाने की हकदार बन गयी है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने तीसरी दुनिया के देशों की आर्थिक स्वायत्तता को नष्ट कर दिया है तथा व्यापक पैमाने पर गैर–बराबरी, और उपभोक्तावादी अपसंस्कृति फैलाई है। अब तो विकसित देश भी इनके कारण बेरोजगारी और उसके फलस्वरूप फैलते सामाजिक तनाव के शिकार हो रहे हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बढता मकडजाल न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनियां में मानवीय संस्कृति और सभ्यता के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। इसलिए इनके खिलाफ चलने वाले इस अभियान में हम सभी एकजुट होकर आवाज उठायेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा कर सकेंगे।

राजीव दीक्षित
सेवाग्राम, वर्धा

Table of Contents

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का इतिहास....6
युद्ध की राजनीति और हथियारों का व्यवसाय....10
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का....15
भारत में प्रवेश....15
उच्च विदेशी तकनीक का झूठ....25
घटते रोजगार और बढ़ती बेरोजगारी....30
गुलाम होती खेती....33
आधुनिक विकास या प्रकृति विनाश....38
संस्कृति पर हमला....40
राजनैतिक हस्तक्षेप....43
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और भारत....54
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का असली चेहरा....59

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मकड़जाल

मानव सभ्यता के विकास के इतिहास में किसी भी नयी खोज ने इतने मनोवेग, गहरे–संदेह, तीखी आलोचना व सनसनी को जन्म नहीं दिया, जितना कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने। जासूसी उपन्यासों का सा रोमांच पैदा करने वाली इनकी रहस्यपूर्ण गतिविधियों की जब कलई खुलती है तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस जगत भी भौचक्का रह जाता है जो कि स्वयं इस तरह की कारगुजारियों का भंडाफोड़ करने का आदी है। रोशनी की एक नीली सी लकीर अन्तर्राष्ट्रीय जगत के उन पुरोधाओं को भी चकाचौध से आँखे भींचने पर मजबूर कर देती है, जो इस मुगालत में रहते है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति उनके इशारों पर संचालित होती है।

आज ऐसे किसी भी बड़े अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विवादों को ढूँढ़ पाना कठिन है जिनके पीछे कहीं न कहीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्वार्थ न जुड़ें हों। किसी आर्केस्ट्रा के संचालक की भाँति ये कम्पनियाँ यह निर्धारित करती है। कि देश के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों एवं नेताओं को किस प्रकार के स्वर निकालने चाहिए। ये कम्पनियाँ उनके प्रति विशेष रूप से निर्मम होती हैं जो उनकी बात नहीं मानते। ऐसे लोगों को सीधे–सीधे उनके पदों से हटा दिया जाता है या उनकी हत्या करवा दी जाती है। इसलिए इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 'सुपर स्टेट' भी कहा जाता है। जिन देशों की ये कंपनियों होती हैं उन देशों की सरकारें भी इनसे भयभीत रहती है क्योंकि ये राज्य के ऊपर एक अधिराज्य के रूप में काम करती हैं। अब 'राज्य की नीति' 'राज्य की शक्ति', 'राज्य की सम्प्रभुता', आदि श्ज्ञब्द अर्थहीन हो गये है। इन कंपनियों की नीतियों से ही अब राज्य की नीतियां निर्धारित होती है। किन्तु विकसित देश इनको बर्दास्त करते हैं और इनका पोषण भी करते है क्योंकि ये कम्पनियां उनके लिए विकासशील व अविकसित देशों का दोहन करती हैं और नये साम्राज्यवाद को बनाये रखती है।

इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आपस में अनिष्टकारी गठजोड़ वास्तव में नयी सम्प्रभु शक्ति है। ये कंपनियाँ विशाल राजनैतिक शक्ति वाले अधिकाधिक स्वाधीन केन्द्र बनते जा रहे है जिन्होंने दुनिया के सभी देशों में राज्य के अन्दर राज्य जैसा कुछ बना लिया है जिसने स्वतन्त्र शक्ति हासिल कर ली है। इन कम्पनियों की ताकत का अनुमान इस बात से ही आसानी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली राज्य भी इन कम्पनियों की अवैध गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकता है। अमेरिका के 'फडरल रिजर्व बोर्ड' को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कितना 'यूरो डालर' कहां और किसके पास है ? और वह अमेरिका में कैसे प्रवेश कराया गया है ? (विदेशों में जमा तरल मुद्रा का भंडार 'यूरा डालर' कहलाता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास करीब 3100 अरब डालर (78,000 अरब रूपये लगभग) की तरल परिसम्पतियाँ बताई जाती है जो विश्व की सभी सरकारों की तरल परिसम्पतियों का लगभग तीन गुना है। इनमें जरा सा भी परिवर्तन करने पर विश्व भर में भयंकर वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है।

सन् 1988 में संसार के कुछ प्रमुख देशों की कम्पनियों ने 10,720 अरब डालर (20,2960 अरब रूपये लगभग) का व्यापार किया। देशों के अनुसार, कम्पनियों के व्यापार का आँकड़ा निम्न है :–

अमेरिका	4807 अरब डालर	(36,526 अरब रू.)
जापान	2843 अरब डालर	(51,174 अरब रू.)
पश्चिम जर्मनी	1201 अरब डालर	(21,618 अरब रू.)
फ्रांस	947 अरब डालर	(17046 अरब रू.)
इटली	828 अरब डालर	(14,904 अरब रू.)
ब्रिटेन	813 अरब डालर	(14,634 अरब रू.)
कनाडा	482 अरब डालर	(8,676 अरब रू.)

(स्रोतः फारचून, जून 1990)

अब राजनैतिक रूप से किसी देश को गुलाम बनाना सम्भव नहीं है। अतः देशों को आर्थिक रूप से इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जरिये गुलाम बनाया जाता है। ये कम्पनियाँ आर्थिक साम्राज्यवादी शोषण का एक प्रमुख हथियार है। किसी भी देश की राजनैतिक व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा। क्योंकि राजनीति अपने आप में कोई एक निरपेक्ष तत्व नहीं है। दूसरी ओर आर्थिक व्यवस्था भी अपने आप में अन्तिम सत्य नहीं है। यदि किसी देश की राजनैतिक व्यवस्था में किंचित परिवर्तन होता है तो आर्थिक होता है तो आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था एक बड़े अनुपात में बदलती है और सामाजीकरण का पूरा ढाँचा ही परिवर्तित हो जाता है। जिससे जीवन मूल्यों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और एक मिश्रित संस्कृति का आविर्भाव होता है जिसके पैर अपनी ही जमीन से उखड़कर किसी दूसरी जमीन की तलाश में होते हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का इतिहास

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जड़े मध्यकाल में वेनिस, अंग्रेज, डच व फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा स्थापित कंपनियों में मिलती हैं। प्राचीन सभ्यता में भी व्यापारियों द्वारा दूसरे देश में जाकर व्यापार करने के उदाहरण मिलते हैं। देश की सीमाओं को लांघकर दूसरे देशों में व्यापार करने के प्रमाण 'मेसोपोटामिया सभ्यता' के समय के मौजूद हैं। लेकिन यह व्यापार मुख्यतः स्वतन्त्र व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता था। व्यापारी समूह बनाकर एक देश से दूसरे देश में अपने माल की बिक्री के लिये जाते थे, और आवश्यकता की वस्तुयें वहां से खरीद कर लाते थे। भारत का रोम के साथ व्यापार, भारत का बर्मा, मलाया (अब मलेशिया), चीन आदि के साथ व्यापार इसी श्रेणी में आता था। रोमन साम्राज्य के समय पार–राष्ट्रीय व्यापार खूब होता था, लेकिन व्यापारियों द्वारा साम्राज्य के पतन के बाद भारत का व्यापार चीन के साथ शुरू हुआ। मुख्यतः दक्षिण भारत का हिस्सा चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियों में अधिक संलग्न था। व्यापार के इस स्वरूप में शोषण की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी और न ही मेजबान व मेहमान देशों के बीच इस व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हुआ करता था।

आधुनिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चरित्र वाली दुनिया की सबसे पहली कम्पनी 'द मस्कोवी कम्पनी' (The Muskovi Compayny) मानी जाती है जिसकी स्थापना सन् 1553 में हुयी थी। इस कम्पनी ने अपनी स्थापना के 3 वर्षों बाद ही दुनिया के महत्वपूर्ण शहरों में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित कर लिये थे। सन् 1553 से 1581 तक 'मस्कोवी कम्पनी' ने अकूत मुनाफा कमाया और सन् 1581 में कम्पनी के अलमबरदारों ने एक और विशालकाय कम्पनी 'द टर्की कम्पनी' (The Turkey Company) को स्थापित कर लिया। इस 'टर्की कम्पनी' की विशेषता थी कि इसने स्थापना के समय ही दुनिया के महत्वपूर्ण नगरों में अपने पाँव पसारे। ऐसा नहीं था कि 1553 से सन् 1581 के बीच दुनिया में किसी अन्य कम्पनी का जन्म ही नहीं हुआ। अन्य कई छोटी कम्पनियाँ सामने आयी लेकिन अधिक दिन तक चल न सकी। अतः यह कहा जा सकता है कि सन् 1553 से सन् 1581 तक 'मस्कोवी कम्पनी' का व्यापारिक क्षेत्र में एकाधिकार रहा।

सन् 1600 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में व्यापार करने के लिये आयी। हालाँकि इस कम्पनी की स्थापना इलिजाबेथ प्रथम के समय में ही हो चुकी थी, लेकिन इस कम्पनी ने बहुराष्ट्रीय चरित्र सन् 1600 में ही ग्रहण किया। भारत आने से पूर्व इस कम्पनी ने दुनियाँ के अन्य हिस्सों में भी पैर जमाने की कोशिश की थी लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। उस समय दक्षिण–पूर्व एशिया में अनेक छोटी–मोटी डच कम्पनियाँ अपना व्यापार कर रहीं थी। भारत में भी कुछ डच कम्पनियों को प्रवेश हो चुका था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सन् 1612 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने डच कम्पनियों के साथ अम्बोनिया (इन्डोनेशिया) में एक युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने एक षड़यन्त्र के तहत डच कम्पनियों के अधिकारियों की सामूहिक हत्या करवा दी। सन् 1667 के आते–आते ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने डच कम्पनियों का नामो–निशान मिटा दिया। सूरत के बन्दरगाह पर कब्जा करने के लिये ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1612 में स्वाली में भी एक युद्ध लड़ा जिसके बाद सूरत के बन्दरगाह पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शिकंजा पूरे देश पर कसता चला गया।

ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से पूर्व, सन् 1670 में स्थापित 'द हडसन बे कम्पनी' (The Hudson Bay Company), सन् 1672 में स्थापित 'द रायल अफ्रीकन कम्पनी' (The Royal African Company) व 1711 में सथापित 'द साउथ सी कम्पनी' (The South Sea Company) आदि विशालकाय बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ दुनिया के तमाम हिस्सों में व्यापार कर रही थी।

सन् 1750 के बाद का दौर ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति का दौर था। जिसके दौरान उत्पादन की तकनीक में आमूल परिवर्तन आया। सन् 1600 से 1750 के बीच अंग्रेजी कम्पनी ने, जिसमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी शामिल थी, अंग्रेजों को अकूत पूँजी का मालिक बना दिया। भारत व दक्षिण–पूर्व एशिया के अन्य देशों का शोषण करके अंग्रेजी बाजार में पैसे का प्रवाह अत्याधिक बढ़ गया। बाजार की ताकतें (बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ) बाजार में ताकतवर होती गयी। मुद्रा का दबाव लगातर बढ़ने का परिणाम औद्योगिक क्रान्ति के रूप में सामने आया।

औद्योगिक क्रान्ति ने व्यापारिक कम्पनियों को जमीन से जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। अधिक उत्पादन व कम लागत के सिद्धान्त के चलते कम्पनियों के मुनाफे बहुत तेजी से बढ़ते गये। सन् 1765 से 1785 के बीच मात्र 20 वर्षों में एक तरफ तो कई नये आविष्कार हुये तथा दूसरी और कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का जन्म हुआ।

सन् 1770 के अकाल में भारत में जहां लाखों लोगों की मौत हो रही थी, वहीं अंग्रेजी जमीन पर वैभव का नंगा नाच हो रहा था। जिस अनुपात में लोग ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा रचाये गये अकाल में मर रहे थे उसी अनुपात में अंग्रेजी साम्राज्य में कम्पनियों तथा आविष्कारों से चमत्कार हो रहे थे। अंग्रेजी बैकों में इतना अधिक धन जमा हो गया था कि उतना धन दुनिया के किसी भ्झी हिस्से में यदि होता तो वहाँ भी औद्योगिक क्रान्ति हो गयी होती।

मात्र 50,000 पाउण्ड से भारत में व्यापार शुरू करने वाली ईस्ट इण्डिया कम्पनी सन् 1770 तक आते–आते भारत से 20,00000 पाउण्ड के बराबर का मुनाफा प्रतिवर्ष कमाती थी। सन् 1860 तक कुछ और विशालकाय बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, जो मूलतः ब्रिटेन की थी, दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थी। इसमें ऐनड्रयू यूल एण्ड कम्पनी, डंकन एण्ड ब्रदर्स कम्पनी (Andrew Yul & Co.), मेक्लाइट एण्ड कम्पनी (Maclite & Co.), बर्न एण्ड कम्पनी, डंकन एण्ड ब्रदर्स कम्पनी (Duncan And Brothers Company), आक्टेवियस स्टील एण्ड कम्पनी (Octavious Steel & Company) गिलान्डर्स अर्बुथनाट एण्ड कम्पनी (Gillanders Arbuthnot Company), शा वालेस कम्पनी (Shaw Wallace Company), ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ थीं, जिनकी 50 से अधिक कम्पनियाँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर रही थीं। इन ब्रिटिश कम्पनियों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिन–जिन देशों में ये कम्पनियाँ व्यापार करने के लिये गयी, उन देशों में अंग्रेजी साम्राज्य का झंडा लहराया गया। ब्रिटिश साम्राज्य की सीमायें बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहां की कम्पनियों ने निभायी थी।

18 वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन की 13 कम्पनियाँ व्यापार कर रहीं थी। बाद में ये क्षेत्र, जिनमें ब्रिटिश कम्पनियाँ व्यापार के नाम पर शोषण कर रही थीं, ब्रिटिश

उपनिवेश बने। इस उपनिवेशों के नाम भी उन्हीं कम्पनियों के नाम पर रखे गये जो इन क्षेत्रों की मालिक बन बैठी थी। उदाहरण के लिये मैसाचुसेट, बोस्टन, लेक्सिग्रंटन, वर्जीनिया, मैरीलैण्ड, जर्सी, पेनसिल्वेनिया आदि जगहों के नाम कम्पनियों के नाम पर रखे गये। जार्ज वाशिंगटन जैसे नेताओं के नेतृत्व में ब्रिटिश उपनिवेशों को मुक्त कराने का राष्ट्रीय आंदोलन अमेरिका में शुरू हुआ। आंदोलन का सबसे ताकतवर पक्ष था, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार। लोगों ने अंग्रेजी कम्पनियों द्वारा बनायी गयी वस्तुओं को खरीदना बंद किया। कम्पनियों को अन्य प्रकार के सहयोग देना छोड़ा। 'असहयोग' और 'बहिष्कार' के नारों से अमेरिकी धरती गूंजी और इस गूंज का परिणाम सन् 1783 में मिला, अंग्रेजी दासता से मुक्ति में। उन 13 अंग्रेजी कम्पनियों को अमेरिका की धरती से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा।

ब्रिटिश कम्पनियों द्वारा जो बीज अमेरिका की धरती छोड़े गये, वे अब पौधे बनने लगे थे। अमेरिका में भी छोटी–छोटी कम्पनियाँ अस्तित्व में आने लगीं थीं। सन् 1865 में अमेरिका का सिविल वार समाप्त हुआ जिसको अमेरिकी औद्योगिक क्रान्ति का नाम दिया जा सकता है। सिविल वार की समाप्ति के बाद अमेरिका उसी नक्शे कदम पर चलने लगा जिस पर कभी ब्रिटेन चला था।

अमेरिका की सबसे पहली बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'सिंगर' (Singer) थी, जो 1867 में स्थापित हुई। इस कम्पनी ने देश के बाहर अपनी पहली उत्पादन इकाई 1867 में ही ग्लासगो (स्काटलैण्ड) में स्थापित की। सन् 1867 में 'बायर' (Bayer) ने अपनी पहली उत्पादन इकाई कोलोन (फ्रांस) में स्थापित की थी जिसमें रासायनिक पदार्थ एनीलीन तैयार किया जाता था। इस कम्पनी के जनक प्रख्यात वैज्ञानिक फ्रेडरिक बायर थे जो जर्मनी के थे। सन् 1866 में विश्वविख्यात भौतिक शास्त्री अल्फ्रेड नोबुल ने डायनामाइट के उत्पादन के लिये 'नोबुल इण्डस्ट्रीज' (Noble Industries) नामक कम्पनी की स्थापना हेम्बर्ग में की। ये तीनों कम्पनियाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ थीं, जो आज अपनी 450 से अधिक कम्पनियों के साथ आर्थिक जगत की बुलंदियों पर हैं। ज्ञात रहे कि दुनिया का प्रतिष्ठित नोबुल पुरस्कार, डायनामाइट व अन्य विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन करने वाली कम्पनी नोबुल इण्डस्ट्रीज द्वारा ही दिया जाता है।

19 वीं शताब्दी की शुरूआत तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आकार व समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि होने लगी थी। अतः यूरोपीय देशों की सरकारों ने संरक्षणवाद की नीति को अपनाया था। जिसके तहत उन देशों की सरकारों ने अपने देश की कम्पनियों को संरक्षण दिया और दूसरे देश की कम्पनियों को अपने बाजार में घुसने पर कई पाबंदिया लगाई। सन् 1890 तक अमेरिका में 5000 कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी थीं। यूरोपीय देशों में उनको घुसपैठ करना अब मुश्किल हो गया था। क्योंकि अधिकतर यूरोपीय देशों में कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। अब इन अमरीकी कम्पनियों ने आपसी प्रतियोगिता से बचने के लिये आपस में ट्रस्ट बनाना शुरू कर दिया। 5000 कम्पनियों में आपस में गठजोड़ हुआ और प्रथम विश्व युद्ध तक आते–आत अमेरिका में 300 विशालकाय कम्पनियाँ देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करके यूरोपीय दशों में भी घुस चुकी थीं। इन 5000 कम्पनियों के आपसी गठजोड़ ने आगे आने वाली कम्पनियों को आपस की प्रतियोगिता से बचने का, एक दूसरे के हितों का आपस में न टकराने का आसान रास्ता दिखाया। जब 5000 कम्पनियों ने आपस में मिलकर 300 विशालकाय कम्पनियाँ स्थापित की तो यूरोपीय देशों में कोहराम मच गया। देशों के आर्थिक प्रतिबन्ध ताक पर धरे रह गये। साम–दाम–दण्ड–भेद की नीति अपनाकर इन कम्पनियों ने यूरोपीय देशों में घुसपैठ की तथा उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अपने अनुरूप बदलकर रख दिया। खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का नारा देकर उन देशों के पुश्तैनी रोजगार

धंधों को चौपट किया। प्रथम विश्वयुद्ध के समय तक बाजी एक दम से पलट गयी थी। कल तक जो ब्रिटेन के हाथ थी अब बाजी अमेरिकी कम्पनियों के हाथ थी। सन् 1901 में ब्रिटेन में काम करने वाली कम्पनियों में सबसे बड़ी कम्पनी (Standard Oil Company) पूरे यूरोप की सबसे बड़ी कम्पनी हुआ करती थी। सन् 1914 तक पूरे यूरोप में जितनी कारें बनती थीं उनमें से एक–तिहाई कार अकेले अमरीका की फोर्ड (Ford) कम्पनी बनाती थी। जबकि इस कम्पनी की स्थापना हेनरीफोर्ड ने सन् 1903 में की थी। प्रथम विश्वयुद्ध के शुरू होने तक अमरीकी कम्पनियों ने यूरोप को रौंद कर रख दिया। इन सन्दर्भ में एफ. ए, मैकेन्जी द्वारा 1902 में लिखित पुस्तक 'द अमेरिकन इन्वेडर्स' अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं। उनके स्वयं के शब्दों में – "अमेरिका ने यूरोप को रौंद दिया हे, अपनी फौंजों से नहीं बल्कि कम्पनियों द्वारा तैयार उत्पादों से। इन कम्पनियों के कप्तान आज यूरोप के भाग्य विधाता बन बैठे हैं। जिन्होंने मैड्रिक से लेकर सेंट्स पीटरबर्ग तक लोगों के दैनिक जीवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इन आततायी कम्पनियों के सामने अब कुछ भी सुरक्षित नहीं रह गया है। हमारे ड्राईवर अमरीकी गाड़ियों की गोद में बैइने को बेताब हैं। हमारे बच्चे अब अमरीकी भोजन पर पल रहे हैं और हमारे बुजुर्ग भी अब अमरीकी ताबूतों में दफनायें जा रहे हैं।" अमरीकी कम्पनियों द्वारा बने सामानों की बाढ़ में यूरोप डूब गया। सुई से लेकर बड़ी–बड़ी मोटर गाड़ियाँ तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल से लेकर, मरने के बाद दफनाने के लिये ताबूत तक अमरीकी कम्पनियों द्वारा बनाये जा रहे थे। सन् 1914 तक कोयला, रेलवे, इस्पात, इन्जीनियरिंग, कार, पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम, रसायन, कपड़ा आदि क्षेत्रों में अमरीकी कम्पनियों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। सन् 1914 तक अमेरिका व यूरोप की कुल तरल परिसम्पत्ति का 90 प्रतिशत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में लगा हुआ था।

युद्ध की राजनीति और हथियारों का व्यवसाय

युद्ध कभी भी राजनीतिक कारणों के लिये नहीं बल्कि आर्थिक कारणों के लिये ही लड़े जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह बात एकदम शीशे की तरह साफ नजर आती है कि इन विशालकाय कम्पनियों के आपसी हित जब टकराते हैं तो उसका परिणाम पूरी मानव जाति को झेलना पड़ता है। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में दखल देने का निर्णय तथी लिया जब उसने देखा कि अमरीकी कम्पनियों के आर्थिक हित चौपट होते जा रहे हैं।

सन् 1914 तक अमरीकी कम्पनियों का यूरोपीय देशों के साथ कुल व्यापार 16.9 करोड़ डालर (वर्तमान समय में लगभग 3.42 अरब रूपये के बराबर) का ाि, जो 1916 तक आते–आते मात्र 11.59 लाख डालर (वर्तमान समय में लगभग 2.08 करोड़ रूपये) रह गया था। यूरोपीय देशो के साथ व्यापार में आयी भारी गिरावट से अमरीकी कम्पनियों को बहुत अधिक घाटा हुआ। अब अमरीकी कम्पनियों ने इस घाटे को पूरा करने के लिये अन्य मित्र देशें में सेंध लगाना शुरू किया और इसमें वे काफी सफल भी रहे। 1914 तक यूरोपीय देशों के बाहर दुनिया के अन्य देशों में अमरीकी कम्पनियों का प्रति वर्ष का कारोबार 82.4 करोड़ डालर था, जो 1916 में बढ़ कर 321.4 करोड़ डालर हो गया था। इस व्यापार में एक बड़ा हिस्सा हथियारों की बिक्री का शामिल था। क्योंकि युद्ध शुरू हो गया था और अमरीकी कम्पनियों ने अब हथियारों का उत्पादन शुरू कर दिया था। युद्धके हालातों में अमरीकी कम्पनियों को हथियारों के व्यापार से अकूत फायदा हुआ। सन् 1916 के बाद हर बड़ी कम्पनी ने अपनी कुल पूँजी का एक बड़ा हिस्सा हथियारों के उत्पादन में लगा दिया था। इस घटना के बाद तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन ने जर्मनी के खिलाफ यह कहकर कि "अधिकार शान्ति से अधिक मूल्यवान है" युद्ध की घोषणा कर दी। पूरे युद्ध के दौरान 375 अरब डालर के हथियार कम्पनियों द्वारा विभिन्न देशों को बेचे गये। अब कम्पनियों के मुँह हथियारों का खून लग चुका था, अतः अब कम्पनियों द्वारा हथियार उत्पादन में सबसे अधिक पूँजी निवेश किया जाने लगा। कई कम्पनियों ने अपने पुराने उत्पादों को बनाना बन्द करके हथियारों का उत्पादन शुरू कर दिया। कई और कम्पनियों ने उपभोक्ता सामग्री के साथ–साथ हथियारों के उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा।

युद्ध के बाद कम्पनियों के कार्य करने के तरीके में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। कम्पनियों ने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिये आपस में मिलकर 'कार्टेल' (कई कम्पनियों को मिलाकर एक समूह) बनाना शुरू कर दिया। बाजारों में आपसी प्रतिद्वन्द्विता से बचने के लिये कम्पनियों ने यह कदम उठाया। प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का समय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इतिहास में 'कार्टेलाईजेशन' के नाम से मशहूर है। अर्थात् शक्तियों का और अधिक केन्द्रीकरण होता गया। पूँजी कुछ केन्द्रों में ही सिमटती गयी। तकनीकी पर कुछ चुनी हुयी कम्पनियों का ही अधिकार होता गया। इस दौर की कुछ प्रमुख कम्पनियाँ जो हथियार उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही थीं और जिन कम्पनियों ने कई अन्य कम्पनियों को अपने में मिलाकर कार्टेल बनाये थे निम्न थीं :–

जनरल मोटर्स, (General Motors), फोर्ड (Ford), स्टैन्डर्ड आयल (Standard Oil), ड्यूपान्ट (Dupont), आई.सी.आई. (I.C.I), एलाइड केमिकल्स (Allied Chemicals), रेमिंगटन (Remington), कैंटर पिलर ट्रैक्टर (Cater Pillar Tractor), क्राइसलर कार्पोरेशन फायर स्टोन (Fire Stone), जनरल इलैक्ट्रीकल्स कार्पोरेशन (General Electricals Corporation), इन्टरनेशनल हार्वेस्टर (International Harvester), कोल्ट (Colt), कोका–कोला (Coca Cola), आई. बी. एम. (I.B.M.), आदि।

द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी रूपरेखा हेड्रिख मुल्लैर द्वारा बनायी गयी थी जिसके तहत पालैण्ड के ऊपर सबसे पहला आक्रमण किया गया। हैड्रिख मुल्लैर, हिटलर के दाहिने हाथ के रूप में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पद पर जर्मन सेना के संचालन के लिये नियुक्त हुआ था।

इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हैड्रिल मुल्लैर क्षितीय विश्व युद्ध के समय कुख्यात बहुराष्ट्रीय कम्पनी आई.टी.टी. का प्रमुख था। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनी युद्ध के समय में फासिस्ट गुट को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। इसके अलावा अपनी सहयोगी कम्पनी 'फोके बुल्फ एयर क्राफ्ट कार्पोरेशन' के साथ मिलकर बमवर्षक विमानों की आपूर्ति फासिस्ट गुट को कर रही थी। सम्पूर्ण युद्ध के दौरान आई.टी.टी. की संचार सेवाओं ने नाजी युद्ध तन्त्र को सीधी सहायता की थी। पर युद्ध समाप्त होते ही यह कम्पनी अमरीकी सेना की भी प्रमुख ठेकेदार बन गयी और इसके अधिकारी मित्र राष्ट्रों के गुप्तचरों के साथ मिलकर घनिष्ठता से काम करने लगे। मजेदार बात यह थी कि आई.टी.टी दोनों ओर से युद्ध में लड़ रही थी। फासिज्म के खिलाफ यह कम्पनी अमरीका व सोवियत संघ को मदद कर रही थी तथा दूसरी ओर नाजी सेनाओं को मदद कर रही थी।

यह अत्यन्त ही विचित्र लगता है कि युद्ध समाप्ति के 30 वर्ष बाद आई.टी.टी. कम्पनी को अमेरिकी सरकार की ओर से 2 करोड़ 60 लाख डालर इस बात की क्षति पूर्ति के लिये प्राप्त हुये कि अमेरिकी वितानों ने जर्मनी में कम्पनी (आई.टी.टी.) के प्रतिष्ठान को भारी नुकसान पहुँचाया था। इस प्रकार आई.टी.टी. ने एक युद्ध के मैदान से तीन–तीन आर्थिक फसलें काटीं। दो बार अपने मुख्यालय के माध्यम से अमेरिका से और एक बार अपनी सहायक कम्पनी के माध्यम से जर्मनी से। यह गौर किया जाना चाहिए कि युद्ध के पूर्व भी इस कम्पनी के जर्मन सेना के गुप्तचर विभाग के प्रमुख गोयरिंग से अत्यन्त ही मधुर सम्बन्ध थे, जिसके कारण कम्पनी के हिटलर के साथ महत्वपूर्ण सम्बन्ध बने थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद अमेरिका की 23 बड़ी कम्पनियों ने नाभिकीय हथियारों को बनाना शुरू किया। इन हथियारों के परीक्षण स्थल बने अफ्रीका व एशियाके गरीब व छोटे देश। हथियारों का उत्पादन करने वाली कम्पनियाँ दि दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगीं। अब यह हथियारों का व्यवसाय कम्पनियों के फलने–फूलने का आधार बना। जो आगे चलकर वियतनाम युद्ध, कोरिया युद्ध, ईरान–ईराक युद्ध व कई अन्य छोटे युद्धों में और अधिक तेजी से फैलता गया।

ईरान के शाह और प्रतिक्रियावादी अरब हुकूमतों ने हथियारों को खरीदने में सैकड़ों अरब डालर खर्च किये हैं। इजरायल, चीन और मिस्र की सरकारें भी हथियारों के बढ़ाव को कायम रखने में सक्रिय रही हैं। इजरायल–मिस्र समझौते के बाद मध्य–पूर्व में अमरीका के सैनिक

औद्योगिक समुच्चय के लिये मुनाफे कमाने की नयी संभावनायें पैदा हो गयी। ईरान व अफगानिस्तान की घटनाओं से भी उन्हें ऐसे ही मौके मिले। जापान और चीन के बीच सम्पन्न तथाकथित शान्ति समझौते ने जिसमें माओवादियों ने, नायकत्ववाद के बारे में एक विरोधी लाबी तैयार की, मित्शूविशी, कावासाकी, हिताची, जोसेन और अन्य विशालकाय जापानी उद्योगों के मुनाफों में भारी वृद्ध कर दी। पीकिंग के दूत कर्जों और हथियारों की तलाश में पश्चिम में सारे देशों को छाने डाल रहे हैं। अभी हाल में अमरीकी यात्रा के दौरान ली पेंग ने लाकहीड, मेकडोनाल्ड–डगलस और बोइंग जैसे दर्शनीय स्थानों में रूचि दिखायी है। उनको श्लेसिंगर, नन और जैकसन जैसे बदनाम युद्धवादियों के द्वारा सैर करायी गयी। बोलीबिया, ब्राजील, चिली, यूनान और इंडोनेशिया में दक्षिणपंथी षड्यन्त्रकारियों को अमरीका सरकार की सलाहकार निगमों ने सहायता पहुँचायी और इसके बदले में इन देशों के सेनाध्यक्षों ने अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध करायी हैं। थल सेना और नौ सेना के लगभग 500 प्रमुख अड्डों और सैनिक हस्तक्षेप के दर्जन से उपर नियंत्रणकारी चौकियों पर दुनिया भर में जहाँ कही भी अमरीकी झंडा गाडा गया है, वहाँ अमरीकी कंपनियाँ घुस गयीं। विश्वव्यापी सैनिक साम्राज्य का निर्माण करना इनके लिये एक अच्छा धंधा रहा है। जबकि इन कंपनियों के समर्थकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां मूलतः एक शान्तिपूर्वक समाज की स्थापना के लिये सुंदर–सुंदर चीजों का निर्माण करने में लगी हुई है। इन कंपनियों का बचाव करने के लिये कितने ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल क्यों न किा जाय, और यह प्रमाणित करने के लिये कितनी ही जी–तोड़ मेहनत क्यों न करें, कि दुनिया में स्थायित्व पैदा हो गया है और राष्ट्रों की हालत में सुधार हो गया है, सैनिक खर्चों में कटौती की गयी है, लेकिन तथ्य उल्टा ही प्रमाणित करते हैं। हाल ही में न्यूयार्क टाइम्स ने अपने एक संपादकीय में लिखा है कि हथियारों का उत्पादन करने और कानूनी तौर पर उनका निर्यात करने में अमरीका की एक हजार से ज्यादा कंपनियाँ लगी हुई हैं। उनमें वे प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं जो दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये जाने जाते हैं। युद्ध सामग्री के निर्माण में एक्सोन (तेल), जनरल मोटस (मोटर), आई.बी.एम. (कम्प्यूटर), आर.सी.ए. (टी.वी. सैट), गुडईयर (टायर), डूयूपोंट (रसायन), सिंगर (सिलाई की मशीनें), वेस्टिंग हाउस (बिजली के सामान) और गल्फ आयल जैसी कंपनियाँ भी शामिल हैं। इन निगमों की कारगहुजारियों के कारण स्थायी शांति नहीं रह पाती। बल्कि सच तो यह है कि ये निगमें लगातार दुनिया को युद्ध के कगार पर खड़ा करने की कोशिश में लगी रहती है।

वियतनाम पर अमरीकी आक्रमण ने विशेष तौर प, उन भ्रांतियों को अधिक धक्का पहुँचाया जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा फैलायी गयी थीं। वियतनामी जनता के लिये इस युद्ध के भयंकर परिणाम सर्वविदित हैं। लेकिन बड़ी संख्या में अमरीकी लोगों को भी हिन्द–चीन के जंगलों में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फायदा हुआ केवल इन बहुराष्ट्रीय निगमों को।

1955 से लेकर वियतनाम युद्ध की समाप्ति तक इन निगमों को हथियारों के 75 प्रतिशत आर्डर प्राप्त हुये। उस काल में अमरीकी सेना की शस्त्रों की आपूर्ति करने वालों की सूची काफी कुछ कहती है– बोईं–1800 करोड़ डालर, जनरल डायनामिक्स– 1400 करोड़ डालर, नार्थ अमेरिकन एवियेशन इन कार्पोरेशन– 1330 करोड़ डालर, यूनाईटेड एयर क्राफ्ट – 1160 करोड़ डालर, जनरल मोटर्स – 1050 करोड़ डालर, डगलस – 850 करोड़ डालर, आई.टी.टी. – 710

करोड़ डालर, मार्टिन मारिये – 660 करोड डालर, ह्यूग्स – 470 करोड़ डालर, मेक्डोनेल – 570 करोड़ डालर, स्पेरी रेंड – 560 करोड़ डालर, रिपब्लिक – 530 करोड़ डालर, ग्रुमेन – 420 करोड़ डालर, बेनडिक्स – 410 करोड डालर, वेस्टिंग हाउस – 390 करोड़ डालर, कर्टिस राइट – 380 करोड डालर, रेथियोन – 330 करोड डालर, आई.बी.एम. – 320 करोड़ डालर। इन निगमों को युद्ध सामुग्री के आर्डरों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस सदस्यों और सीनेटरों की मद से मिला था।

इजरायल भी इस बात को स्वीाकरने लगा है कि "मिसाइलों का व्यापार संतरों से अधिक लाभदायक है" – ये शब्द वहां के प्रधानमंत्री ने हाल में ही व्यक्त किये है। इजरायल हथियारों को बेचने में समर्थ है। वहाँ इन हथियारों का उत्पादन 'राकवेल', 'लाकहीड', 'वानिया', 'जेनिथ', 'वेस्टिंग हाउस', 'मफीनबोल', 'मेग्रावोक्स', 'एयरोजोट', 'जनरल न्यूक्लियोनिक्स', 'लिंग–टेक्को–वोग्ट' आदि निगम कर रहे है। इजरायल के शस्त्र उद्योग के संरक्षकों में ड्यूश बैंक, एत्रजीत्र शामिल हैं जो पश्चिम जर्मनी के सबसे बड़े बैंकों में से एक हैं। यह बैंक वहाँ के निगमों को वित्त मुहैया कराता है। पिछले 10–12 वर्षो में यहाँ के निगमों के निर्यात में 50 गुना वृद्धि हुई है। आज यह निर्यात 100 करोड़ मार्क को पार कर चुका है। ये निगम जेट (लड़ाकू बमवर्षक), आस्टंड – 1124 (समुद्र तटीय गश्ती विमान), फौगा – माजिस्टर (बमवर्षक), अरावा (सैनिक परिवहन विमान), जहाज से छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र, 155 एम.एम. तोपें, प्रक्षेपास्त्र ढाने वाले जहाज तक बेचते है। प्रिटोरिया की सरकार इनके मुख्य ग्राहकों में से एक हैं।

नाभिकीय हथियारों को बनाने की प्रौद्योगिकी को बेचना विशेष रूप से विनाशकारी है। दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य में नाभिकीय हथियारों का विकास इन निगमों की सहायता से किया जा रहा है। ये जनता की माँग को अनदेखा करके उनके उत्पादन में जुटे हैं। ये निगमें उन मानदण्डों तक का उल्लंघन करती है जिनको सरकारें मानती हैं अभी हाल में अर्जेटीना को एक निगम द्वारा नाभिकीय संयंत्र और प्रोद्योगिकी बेचने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि अर्जेटीना की सरकार इस बात की समुचित गारंटी नहीं दें रही थी कि उक्त संयंत्र का उपयोग सैनिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जायेगा, पर फिर भी पश्चिम जर्मनी के निगम ने उस सरकार को प्रौद्योगिकी व रियेक्टर दोनों बेचे।

दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार के बाद पश्चिम जर्मनी में सामरिक राकेटों का विकास करने और इनका निर्माण करने पर रोक लगा दी गयी थी परन्तु ओ.टी.आर.ए.जी. कंपनी की पारराष्ट्रीयता का लाभ उइाते हुये इस निगम से कुछ नहीं कहा गया। फिर पश्चिम जर्मनी को यह विचार आया कि प्रक्षेपास्त्र व्यापार किसी अन्य देश की धरती से किया जा सकता है, अतः इस कंपनी ने जायरे में एक क्षेत्र की रियासत हासिल कर ली और प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र का विकास कर लिया। जनता के सामने इस पूरे सौदो को व्यापारिक कह कर प्रस्तुत किया गया। अब जायरे के उस क्षेत्र का इस्तेमाल सारे अफ्रीका को धमकाने के लिये किया जा रहा है। हथियारों का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नीति का एक मूल अंग है। वे इसको मेहनतकश जनता की कीमत पर मुनाफों का एक स्थायी स्रोत मानती हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 से लेकर 1969 के बीच अमेरिकी कम्पनियों का विश्व व्यापारी पूँजी निवेश 72 अरब डालर से बढ़कर लगभग 708 अरब डालर हो गया। जिसके

परिणाम स्वरूप विश्व भर के कुल पूँजी निवेश का 65 प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी कम्पनियों के पास हो गया।

इसके अतिरिक्त सन् 1952 के बीच में अमेरिका में बनी मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों को अपने बाजारों को विकसित करने हेतु 17 अरब डालर की अतिरिक्त अमेरिकी सहायता दी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप की प्रति व्यक्ति आय नाटकीय तरीके से बढ़ गयी। मार्शल योजना की यह सफलता थी, जिसके कारण यूरोपीय बाजार में अमरीका की वस्तुओं की मांग और अधिक बढ़ गयी। अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का वास्तविक रूप सन् 1952 में देखने को मिला। विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता गरीब देशों में बाजार पैदा करने के काम आती है, न कि उन देशों का विकास करने में। यूरोपीय अर्थशास्त्री रेमन्ड वर्नोन ने योजना पर टिप्पणी करते हुये कहा था । "अमेरकिा के लिये मार्शल योजना एक ऐसा राजनीतिक हथियार है, जिससे वह अपने देश की कम्पनियों को यूरोप में चल रहे आर्थिक युद्ध में सम्पूर्ण विजय की ओर ले जा रहा है और दुनिया में अमेरिकी आर्थिक–आधिपत्य की जड़ों को मजबूत कर रहा है। इस मार्शल योजना के दूरगामी परिणाम होंगे। दुनिया के अन्य गरीब देश भी अमेरिकी मदद पाने के लिये एक दूसरे से होड़ करेंगे जिसकी वजह से उनका सही विकास अवरूद्ध होगा और वे एक ऐसे विकास के रास्ते पर धकेल दिये जायेंगे जहां से वापस लौटना उन गरीब देशों के लिये फिर असम्भव होगा।"

सन् 1960 के आते–आते रेमन्ड बर्नोन द्वारा की गयी भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुयी। एशिया व अफ्रीका के देशों में विदेशी मदद के बहाने अमेरिकी व अन्य यूरोपीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ बढ़ने लगी। अब गरीब देशों को आर्थिक मदद देना अमेरिका की रणनीति बन गयी। आने वाली अमेरिकी सरकारों ने इस परम्परा को लगातार आगे बढ़ाया।

यूरोपियन आर्थिक समुदाय का गठन इसी दशक में हुआ। जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कम्पनियों के यूरोप में बढ़ते प्रभाव को कम करने तथा यूरोपीय कम्पनियों को आगे बढ़ाने के लिये था। इसमें यूरोपीय देश आंशिक रूप से सफल रहे। क्योंकि अधिकतर यूरोपीय देशों के पास विदेशी मुद्रा (डालर) का अभाव था। लेकिन यूरोपियन आर्थिक समुदाय के गठन के बाद यूरोपिय बाजार आर्थिक उतार–चढ़ाव के दौर के बाद स्थिर होने लगा इसी दौर में यूरोपियन कम्पनियों का उदय हुआ। हालांकि कुछ यूरोपियन कम्पनियाँ तो इस शताब्दी के शुरूआती दौर में ही अस्तितत्व में आ चुकी थी। लेकिन सन् 1960 और उसके बाद यूरोपीय कम्पनियाँ भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजर पर छाने लगीं। सन् 1970 व इसके बाद का दौर जापानी कम्पनियों के उदय का था।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारत में प्रवेश

भारत में विदेशी कम्पनियाँ तीन तरीके से कम कर रही है। पहला, सीधे अपनी शाखायें (Branch) स्थापित करके, दूसरा अपनी सहायक कम्पनियों (Subsidiaries) के माध्यम से, तीसरा देश की अन्य कम्पनियों के साथ साझेदार कम्पनी (Colaboration) के रूप में।

जून 1995 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 3500 से कुछ अधिक विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, अपनी शाखाओं या सहायक कम्पनियों के रूप में देश में घुसकर व्यापार कर रही हैं। 20,000 से अधिक विदेशी समझौते देश में चल रहे हैं। औसतन 1000 से अधिक नये विदेशी समझौते प्रतिवर्ष देश में होते हैं।

सन् 1972 के अन्त तक देश में कुल 740 विदेशी कम्पनियाँ थीं। जिनमें से 538 अपनी शाखायें खोलकर व 202 अपनी सहायक कम्पनियों के रूप में काम कर रही थीं। इनमें सबसे अधिक कम्पनियाँ ब्रिटेन की थीं। लेकिन आज सबसे अधिक कम्पनियाँ अमेरिका की हैं। समझौते के अन्तर्गत काम करने वाली सबसे अधिक कम्पनियाँ जर्मनी की हैं। 1977 में विदेशी कम्पनियों की संख्या 1136 हो गयी।

आजादी के पूर्व सन् 1940 में 55 विदेशी कम्पनियाँ देश में सीधे कार्यरत थीं। आजादी के बाद सन् 1952 में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार ब्रिटेन की 8 विशालकाय कम्पनियों के सीधे नियन्त्रण में 701 कम्पनियाँ भारत में व्यापार कर रही थीं। ब्रिटेन की अन्य 32 कम्पनियाँ, भारतीय कम्पनियों के साथ किये गये समझौतों के तहत कार्यरत थीं। ये 8 विशालकाय ब्रिटिश कम्पनियाँ सन् 1853 से ही भारत में घुसना शुरू हो गयी थीं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत लायी गयी ये कम्पनियाँ सन् 1860 तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारतीय उपमहाद्वीप के शोषण के लिये धारदार हथियार बन चुकी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित हो जाने के बाद ये कम्पनियाँ दुनिया के अन्य दूसरे देशों में शोषण करने चली गयीं।

ये 8 ब्रिटिश कम्पनियाँ निम्न थीं :–

1. एन्ड्रयूल एण्ड कम्पनी
2. मेक्लाइड एण्ड कम्पनी
3. मार्टिन एण्ड कम्पनी
4. बर्न एण्ड कम्पनी
5. डंकन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी
6. आक्टेवियस स्टील एण्ड कम्पनी
7. गिलैण्डर अर्बुदनाट एण्ड कम्पनी
8. शा वालेस एण्ड कम्पनी

भारत में जैसे–जैसे विदेशी पूँजी का निवेश बढ़ता गया वैसे–वैसे विदेशी कम्पनियों की संख्या बढ़ती गयी। इसके साथ जुड़ा हुआ एक आश्चर्यजनक सत्य यह है कि जिन विदेशी कम्पनियों ने भारत में पूँजी निवेश किया उनमें से अधिकांश कम्पनियों ने अपने निवेश करने के अगले वर्षों में ही अपनी निवेश की हुयी पूँजी के बराबर या उससे अधिक पूँजी कमा ली। बाकी अन्य कम्पनियों ने अधिकतम 5 वर्षों में अपनी निवेश की हुई पूँजी को कमा लिया।

हर क्षेत्र में घुसी हैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ

आज देश का छोटा–बड़ा प्रत्येक क्षेत्र इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गुलाम है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आने वाली कोई भी चीज ऐसी नहीं हैं, जिसे ये कम्पनियाँ न बनाती हों। दैनिक उपयोग के सामानों का उत्पादन करके ये विदेशी कम्पनियाँ घर–घर में घुसी हुयी हैं। खेती के काम में आने वाले जहरीले कीटनाशकों, खादों अन्य उपकरणों का उत्पादन करके इन विदेशी कम्पनियों ने हमारी आत्मनिर्भर खेती को अपना गुलाम बना लिया है। उद्योगों के क्षेत्र में रद्दी तकनीकी का इस्तेमाल करके वातावरण को विषैला कर दिया है। हवा, पानी और मिट्टी भी अब प्रदूषण से मुक्त नहीं हैं।

नीचे उन क्षेत्रों की सूची दी गयी है जिनमें घुसकर इन विदेशी कम्पनियों में हमारी आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना दिया है–

कुछ प्रमुख उत्पादन के क्षेत्र, जिनमें विदेशी कम्पनियाँ घुसी हुई हैं।

1. दैनिक उपभोग की सामग्री के क्षेत्र में
2. दवा उद्योग के क्षेत्र में
3. खाद, कीटनाशक, दवायें व खेती उपकरणों के क्षेत्र में
4. रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में
5. मोटर–गाड़ियों के उपकरणों के उत्पादन के क्षेत्र में
6. भारी इंजीनियरिंग सामानों के उत्पादन के क्षेत्र में
7. इलेक्ट्रानिकी व इलैक्ट्रीकल सामानों के उत्पादन के क्षेत्र में
8. सैनिक रक्षा सामग्री के क्षेत्र में
9. फूड प्रोसेसिंग व प्लांटेशन (चाय, कॉफी, डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थ, चॉकलेट)
10. वैज्ञानिक रक्षा अनुसंधान में
11. सीमेन्ट उद्योग में
12. तेल शोधन व उत्पादन के क्षेत्र में
13. धातुओं के खनन तथा निष्कर्षण क्षेत्र में
14. जूट उद्योग में
15. सिले हुये (रेडीमेड) कपड़ों के उत्पादन क्षेत्र में
16. जूते व अन्य खेल सामानों के उत्पादन क्षेत्र में
17. रबर इन्डस्ट्रीज के क्षेत्र में
18. बच्चों के खिलौने व अन्य प्लास्टिक सामानों के उत्पादन में

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ताकत

भारत में इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कितनी ताकत है ? इनकी ताकत का एक अंदाज इसी बात से लागया जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी विशालकाय (Giants) 100 बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ चुनी गयीं हैं। जिनके बारे में 'फारचून' पत्रिका के 31 जुलाई 1989 के अंक में एक टिप्पणी छपी थी :–

"पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर चुनी गयी 100 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा है। जितनी तरह परिसम्पत्ति इन 100 कम्पनियों के पास हैं, उसमें जरा सी भी हेर–फेर कर देने पर पूरे विश्व की अथव्यवस्था चरमरा सकती है।" इन सभी कम्पनियों की शाखायें दुनिया के 125 से भी अधिक देशों में है। 31 जुलाई 1995 तक इन 100 कम्पनियों में से 50 कम्पनियाँ भारत में काम कर रही हैं। इन 50 कम्पनियों में से प्रत्येक का वार्षिक कारोबार भारत सरकार के वार्षिक बजट से अधिक है।

वर्ष 1994 में इन कम्पनियों की विश्व भर में बिक्री तथा भारत में ये कम्पनियाँ किस रूप में कार्य कर रहीं हैं; इसका विवरण नीचे दी गयी तालिका में दिखाया गया है :–

वि कम्पनी देशी/बहुराष्ट्रीय	वर्ष 1994 की बिक्री	भारत में कार्यरत रूप
जनरल मोटर्स	4936.032 अब्ज रुपये	शाखा
फोर्ड मोटर्स	4110.048 अब्ज रुपये	शाखा
एक्सॉन	3246.688 अब्ज रुपये	शाखा
वॉल मार्ट	2669.184 अब्ज रुपये	शाखा
ए.टी. ॲण्ड. टी.	2403.008 अब्ज रुपये	शाखा
जनरल इलेक्ट्रिक क.	2063.984 अब्ज रुपये	शाखा
आई. बी. एम	2049.664 अब्ज रुपये	शाखा
मोबिल	1907.872 अब्ज रुपये	शाखा
सीयर्स	1745.888 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्यम में
क्राइसलर	1671.168 अब्ज रुपय	संयुक्त उद्यम में
स्टेट फॉर्म	1234.200 अब्ज रुपये	–––––––––
प्रूडेन्शियल कंपनी	1163.072 अब्ज रुपये	सहयोगी कम्पनी
ई. आई. द्यूपौं	1118.976 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्यम/
मार्ट	'1098.016 अब्ज रुपये	–––––––––
सीटीकॉर्प	1012.800 अब्ज रुपये	शाखा
शेवरॉन	994.048 अब्ज रुपये	सहयोगी कंपनी
प्रॉक्टर एंड गॅंबल	969 अब्ज रुपये	शाखा
पेप्सीको	911 अब्ज रुपये	शाखा/संयु उद्योग
ऑमको	862 अब्ज रुपये	सहयोगी कंपनी
हेलवट पॅकार्ड	799 अब्ज रुपये	शाखा/सह. कंपनी
आय. टी. टी.	760 अब्ज रुपये	शाखा/सह. कंपनी

कोनाग्रा	752 अब्ज रुपये	सहयोगी कंपनी
क्रोजर	734 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्योग
अमेरिकन इंटरनॅशनर ग्रुप	716 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्योग
मोटोरीला	711 अब्ज रुपये	शाख/संयु. उद्योग
मेट्रोपॉलीटन लाईफ	712 अब्ज रुपये	शाखा/संयु उद्योग
इन्शूरन्स कंपनी		
फिलीप मॉरिस	1720 अब्ज रुपये	शाखा
टेक्साको	1080 अब्ज रुपये	सहयोगी कंपनी
बोइंग कॉरपोरेशन	701 अब्ज रुपये	शाखा/संयु उद्योग
डायटन–हडसन	681 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्योग
युनायटेड टेक्नॉलॉजी	626 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्योग
जे. सी. पेनी	674 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्योग
डाऊ केमीकल्स	640 अब्ज रुपये	शाखा/संयु उद्योग
जी. टी. ई. स्टेमफोर्ड	638 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्योग
युनायटेड पार्सल सर्विस	626 अब्ज रुपये	शाखा
फेडरेशन नॅशनल मॉरगेज		
ॲसोसिएशन ट्रॅव्हलर्स	590 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्योग
सिग्न	588 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्योग
अमेरिकन स्टोअर्स	587 अब्ज रुपये	शाखा
मेरिल लिन्ब	583 अब्ज रुपये	शाखा
जेरॉक्स	570 अब्ज रुपये	शाखा
ॲटना लाईफ इन्शुरन्स कंपनी	560 अब्ज रुपये	——————
ईस्टमॅन कोडक	539 अब्ज रुपये	शाखा
बेलसाउथ	539 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्योग
यू.एस. एक्स.	537 अब्ज रुपये	शाखा/संयु उद्योग
बॅंक ऑफ अमेरिका	528 अब्ज रुपये	शाखा
प्राइस–कॉस्टको	527 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्योग
कोका–कोला	517 अब्ज रुपये	शाखा/संयु उद्योग
ए. एम.आर.	516 अब्ज रुपये	संयुक्त उद्योग
सुपर व्हॅल्यू	509 अब्ज रुपये	शाखा

विदेशी पूँजी का धोखा

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जब भी दुनिया के किसी देश में व्यापार करने के लिये जाती हैं तो वे उस देश के लिये भारी सिर दर्द बन जाती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के किसी भी देश में काम करने से ऐसा नहीं है कि मात्र आर्थिक दुष्प्रभाव ही पड़ते हों अपितु उस देश में इन कम्पनियों के व्यापक और गहरे प्रभाव नजर आते हैं। क्योंकि इन कम्पनियों का चरित्र ही ऐसा है कि ये देश की नीतियाँ बदलवाने के लिये सीधे राजनैतिक हस्तक्षेप करती है। सामाजिक जीवन भी इन कम्पनियों के प्रभाव से अछूता नहीं रहता है।

जब ये कम्पनियाँ काम करने के लिये अन्य देशों में जाती हैं तो उनके पीछे कुछ मिथ्या धारणायें काम करती हैं जैसे ये अपने साथ पूँजी लायेंगी, आधुनिक तकनीक देंगी, लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करायेंगी, देश का निर्यात बढ़ायेंगी, देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति को चुस्त–दुरूस्त रखेंगी, देश की आर्थिक संसाधनों में और अधिक वृद्धि करेंगी आदि–आदि। लेकिन असलियत ठीक इन सभी दावों से उल्टी होती है।

विदेशी कम्पनियों के पक्ष में सबसे बड़ी दलील दी जाती है कि भारत जैसे गरीब और पिछड़े देश में पूँजी की बड़ी कमी होती है और पूँजी के अभाव में विकास नहीं हो सकता। इसलिये विदेशों से पूँजी आमन्त्रित करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है और पिछड़ेपन के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है।

लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये विदेशी कम्पनियाँ बाहर से बहुत कम पूँजी लाती है, अधिकांश पूँजी यहां के बैंकों से कर्ज लेकर, यहाँ की जनता से कर्ज लेकर और उनको शेयर बेचकर एकत्रित करती हैं। देश में जितनी भी विदेशी कम्पनियाँ कार्य कर रही हैं, वे औसतन 5 प्रतिशत तक पूँजी ही बाहर से लाती है। बाकी 90 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक पूँजी ये भारतीय स्रोतों से ही एकत्रित करती हैं।

कितनी पूँजी, कितना धोखा

भारत में व्यापार कर रही 45 प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने जब व्यापार शुरू किया तो कितनी पूँजी लगायी थी, इसके बारे में कुछ तथ्य नीचे दिये जा रहे हैं :–

बहुराष्ट्रीय कम्पनी	आने का वर्ष	लायी गयी पूँजी
शालीमार पेन्टस लि.	1901	63 लाख रुपये
बी.एस.टी. इंन्डस्ट्रीज लि.	1930	1.85 कोटी रुपये
बाटा इण्डिया लि.	1931	70 लाख रुपये
हिन्दुस्थान लीवर लि.	1933	24 लाख रुपये
युनियन कार्बाईड इण्डिया लि.	1934	8.36 कोटी रुपये
क्रॉम्प्टन ग्रीव्स लि.	1937	3 कोटी रुपये

न्यू इन्डीया इंडस्ट्रीज लि.	1942	27 लाख रुपये
बूट्स कंपनी इंडिया लि.	1943	1.10 कोटी रुपये
जॉफ्रीमॅन कंपनी लि.	1943	5 लाख रुपये
क्लोराइड इंडिया लि.	1946	2.11 कोटी रुपये
ब्यूको वुल्फ इंडिया लि.	1947	39 लाख रुपये
बेकेलाईट हायलम लि.	1947	1 कोटी रुपये
हिन्दुस्थान सीबा गायगी लि.	1947	4.57 कोटी रुपये
सायनामिड इंडिया लि.	1947	1.39 कोटी रुपये
कोटस् इंडिया लि.	1947	38 लाख रुपये
जर्मन रेमेंडीज लि.	1949	64 लाख रुपये
मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लि.	1951	3.35 कोटी रुपये
ओटीस वलीवेटर कंपनी लि	1953	72 लाख रुपये
कार्बोरेंडम युनीव्हर्सल लि.	1954	1.06 कोटी रुपये
फेनर इंडिया लि.	1955	64 लाख रुपये
हेक्स्ट इंडिया लि.	1956	2.72 कोटी रुपये
केबल कार्पोरेशन इडिया	1956	3.40 कोटी रुपये
इंग्लिश इलेक्ट्रीक कंपनी	1956	2.25 कोटी रुपये
सीमेन्स इंडिया लि.	1956	2.40 कोटी रुपये
पॉलीकेम लीमिटेड	1956	56 लाख रुपये
डॉ. बँक अँन्ड कंपनी लि.	1956	16 लाख रुपये
जॉन्सन अँन्ड जॉन्सन लि.	1957	24 लाख रुपये
कलर केम लि.	1957	1.25 कोटी रुपये
बायर इंडिया लि.	1957	3.59 कोटी रुपये
फूड स्पेशॅलिस्ट लि.	1958	4.51 कोटी रुपये
डेव्हीर्चड ब्राउन ग्रिव्हज लि.	1959	36 लाख रुपये
ॲटलास कापको इंडिया लि	1959	1.33 कोटी रुपये
के. एस. बी. पंप्स लि.	1959	86 लाख रुपये
मॅथर अँड प्लॅंट लि.	1959	1.83 कोटी रुपये
फिलिप्स कार्बन ब्लॅक लि.	1959	1.57 कोटी रुपये
सँडविक एशिया लि.	1960	1.17 कोटी रुपये
ऑडको इंडिया लि.	1961	12 लाख रुपये

किर्लोस्कर कमिन्स लि.	1961	50 लाख रुपये
आय. डी. एल. केमीकल्स लि.	1961	1.07 कोटी रुपये
गेस्ट कीन विलियम्स लि.	1962	7.69 कोटी रुपये
सुन्दरम क्लोटन लि.	1962	1.96 कोटी रुपये
रिचर्डसन हिंदुस्थान लि.	1964	1.17 कोटी रुपये
नीडल रोलर बेअरिंग कंपनी	1965	10 लाख रुपये
विडिया इंडिया लि.	1965	45 लाख रुपये
सेन्चूरी एन्का लि.	1965	2.97 कोटी रुपये

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पूँजी निवेश मात्र एक धोखा है। हिन्दुस्तान लीवर, कालगेट, सीबागाइगी जैसी सैकड़ों विदेशी कम्पनियों ने मात्र कुछ लाख रूपये से भारत में व्यापार शुरू किया। लाभ कमा–कमा कर बोलस शेयर के रूप में इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपनी शेयर पूँजी कराड़ों रूपये में कर ली। अब ये कम्पनियाँ रॉयल्टी, शुद्ध लाभ और टक्नीकल फीस के रूप में अरबों रूपये भारत से बाहर ले जा रही हैं। इस बात की गंभीरता का अहसास इसी से हो जाता है कि 1976.77 में जहाँ भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियाँ 121.54 करोड़ रूपये देश से बाहर ले गयीं, वहीं 1986–87 में यह राशि बढ़कर 494.6 करोड़ रूपये हो गयी। पिछले 11 वर्षों में ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वैधानिक रूप से 3244.15 करोड़ रूपये भारत से बाहर ले जा चुकी हैं, जबकि अवैधानिक तरीके से ये कम्पनियाँ इससे कई गुनी अधिक राशि देश से बाहर ले जा चुकी हैं। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भारत में शेयर पूँजी लगभग 675 करोड़ रूपये मात्र है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ देश के खून–पसीने की कमाई विदेशी मुद्रा का निर्यात अपने मूल देशों को कर रही हैं। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने पूँजी के नाम पर कैसा मकड़जाल इस देश पर फैलाया है, इसका अनुमान दो–तीन उदाहरणों से लगाया जा सकता है।

हिन्दुस्तान लीवर ने भारत में सन् 1933 में जब व्यापार शुरू किया तब इसकी मूल कम्पनी यूनीलीवर ने मात्र 24 लाख रूपये लगाये। 1933 में प्रारम्भ हुयी इस कम्पनी ने ऐसा जाल बिछाया कि 1990 में इसकी मूल कम्पनी यूनीलीवर की शेयर पूँजी 47.59 करोड़ रूपये हो गयी। इसमें से 44.51 करोड़ रूपये की शेयर पूँजी बोनस के रूप में जुड़ी। 1975 से 1990 तक के बीच हिन्दुस्तान लीवर ने 80.18 करोड़ रूपये लाभांश के रूप में भारत से बाहर भेज दिये। यह रकम रायल्टी और तकनीकी शुल्क के अतिरिक्त है।

इसी तरह कालगेट–पामोलिव कम्पनी ने सन् 1937 में मात्र 1.5 लाख रूपये से अपना कारोबार शुरू किया। 1989 के आते–आते अमरीकी कम्पनी कालगेट–पामोलिव की शेयर पूँजी बढ़कर 12.57 करोड़ रूपये हो गयी। इसमें 12.56 करोड़ रूपये की पूँजी बोनस शेयर के रूप में जुड़ी। कालगेट–पामोलिव कम्पनी 1977 से 1989 के बीच में 18.42 करोड रूपये लाभांश के रूप में भारत से अमरीका ले गयी।

स्विस कम्पनी सीबा गाइगी ने 1947 में 48.75 लाख रूपये से कारोबार शुरू किया। 1991 में इस कम्पनी की शेयर पूँजी बढ़कर 13.54 करोड़ रूपये हो गयी। इलैक्ट्रानिक उद्योग में लगी फिलिप्स कम्पनी ने 1956 में सिर्फ 10 लाख रूपये में अपना कारोबार शुरू किया, सन् 1974 में इस कम्पनी ने 10 करोड़ रूपये मुनाफे के रूप में भारत से होलैण्ड भेज दिया। रिजर्व बैंक की 1992 की रिपोर्ट के अनुसार 1987–88 में 326 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शेयर पूँजी 1445.23 करोड़ रूपये थी, इनमें 60 प्रतिशत हिस्सा भारतीय लोगों का हुआ था, 610 करोड़ रूपये बैंकों के थे और 50 करोड़ सरकार के थे।

सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जितनी पूँजी लेकर आती है, उससे कई गुना अधिक पूँजी तो वे एक ही वर्ष में देश के बाहर भेज देती हैं। उदाहरण के लिये गुडईयर कम्पनी ने भारत में 1 करोड़ रूपये पूँजी का निवेश किया। यह पूँजी निवेश इस कम्पनी ने भारत में अपना कारोबार शुरू करने पर किया था। लेकिन 1989 में गहुडईयर ने 7.33 करोड़ रूपया भारत से बाहर मुनाफे के रूप में भेज दिया। अर्थात् एक ही वर्ष में पूँजी निवेश का सात गुना देश से बाहर भेज दिया। इसी तरह बायर इंडिया का भारत में आरम्भिक पूँजी निवेश 8.29 करोड़ रूपये था, लेकिन 1989–90 में ही इस कम्पनी ने 13.3 करोड़ रूपये मुनाफे के रूप में भारत से बाहर भेज दिये। ग्लैक्सो इंडिया की भारत में चुकता पूँजी 2.88 करोड़ रूपये की है, लेकिन इस कम्पनी ने 1989–90 में 3.93 करोड़ रूपये मुनाफे के रूप में देश से बाहर भेज दिये। अमरीकी कम्पनी फाइजर ने, भारत में जब अपना कारोबार शुरू किया तो मात्र 5 लाख रूपये लगाये और कारोबार शुरू होने के पहले ही वर्ष में फाइजर ने 4.83 करोड़ रूपये भारत से अमरीका भेज दिया। इसी तरह अमरीकी कम्पनी एबट लेबोरेटरीज ने मात्र 1 लाख रूपये की पूँजी से कारोबार शुरू करके, अगले ही वर्ष में 23 लाख रूपये भारत से अमरीका भेज दिया। ग्रेशम एण्ड कविन कम्पनी अपनी चुकता पूँजी का 7.65 गुना मुनाफा हर साल विदेश ले जाती है। सिगरेट बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी आई.टी.सी. अपनी कुल चुकता पूँजी पर लगभग 11364 प्रतिशत मुनाफा कमा रही है। लगभग सभी अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपनी चुकता पूँजी का 860 प्रतिशत मुनाफा भारत से कमा रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ मुनाफे, लाभांश, रॉयल्टी और तकनीकी फीस के रूप में कितना धन देश से बाहर ले जा रही है, इसकी जानकारी के लिये नीचे तालिका दी गयी है :–

कितना लूट कर ले जा रही हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ

वर्ष	मुनाफे के रूप में (करोड़ रू.)	लाभांश के रूप में (करोड़ रू.)	रायल्टी के रूप में (करोड़ रू.)	तकनीकी फीस के रूप में (करोड़ रू.)
1965–66	13.50	19.40	2.95	6.98
1966–67	14.47	28.77	5.13	10.43
1967–68	15.95	32.70	4.32	14.68
1968–69	12.96	30.25	4.78	17.97
1969–70	12.72	31.14	5.80	13.05

1970–71	13.12	43.48	5.23	20.63
1971–72	09.94	38.87	5.86	13.90
1972–73	15.54	39.08	7.33	11.33
1973–74	21.91	37.51	6.21	14.08
1974–75	07.19	18.46	8.46	12.56
1975–76	20.36	24.84	10.49	25.66
1976–77	19.39	48.47	15.88	37.88
1977–78	10.13	68.01	19.50	28.14
1978–79	10.24	54.35	12.65	55.52
1979–80	14.37	50.92	9.53	43.97
1980–81	12.10	55.92	8.88	104.93
1981–82	12.16	58.92	15.99	270.70
1982–83	19.12	70.31	39.72	258.58
1983–84	20.00	62.11	27.60	314.89
1984–85	16.68	74.58	28.49	300.90
1985–86	11.80	75.20	23.50	367.90
1986–87	10.60	85.50	40.10	358.40

स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया रिपोर्ट 1989

सन् 1978 में भारत में कुल विदेशी पूँजी का निवेश 1800 करोड़ रूपये था जो भारत में कुल पूँजी निवेश (नीजि तथा सरकारी क्षेत्रों में) का मात्र 8 प्रतिशत था। जबकि दूसरी ओर इसी वर्ष दो के 1929 करोड़ रूपये बाहर चला गया इन कम्पनियों के लाभ, रायल्टी, तकनीकी फीस, इत्यादी के रूप में।

नीचे दी गयी तालिका सन् 1981 में देश में विदेशी पूँजी निवेश तथा साथ ही साथ उसी वर्ष में देश से बाहर जाने वाली पूँजी का आंकड़ा दिया गया है :–

वर्ष	विदेशी पूँजी निवेश	भारत से बाहर गया धन
1981	108 करोड़ रूपये	114 करोड़ रूपये
1982	628 करोड़ रूपये	641 करोड़ रूपये
1983	618 करोड़ रूपये	590 करोड़ रूपये
1984	1130 करोड़ रूपये	1169 करोड़ रूपये
1985	1260 करोड़ रूपये	1181 करोड़ रूपये
1986	1066 करोड़ रूपये	1265 करोड़ रूपये
1987	1077 करोड़ रूपये	1193 करोड़ रूपये
1988	2397 करोड़ रूपये	2542 करोड़ रूपये
1989	3166 करोड़ रूपये	5235 करोड़ रूपये

1991 से	25,479 करोड़ रूपये	34240 करोड़ रूपये
1995 तक		

ऊपर दिये गये आंकड़ो से एकदम स्पष्ट है कि वर्ष 1983 व 1985 को छोड़कर शेष वर्षों में देश को घाटा ही रहा है। जितना पूँजी निवेश हुआ, उससे कहीं अधिक धन देश से बाहर चला गया। अतः स्पष्ट है कि विदेशी पूँजी निवेश का सौदा देश के लिये घाटे का सौदा रहा।

उच्च विदेशी तकनीक का झूठ

विदेशी उच्च तकनीक को लाने के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को व्यापार की खुली छूट दी जाती है। भारत में आने वाली सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने विदेशी उच्च तकनीक देने के समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। लेकिन वास्तव में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ऐसे क्षेत्रों में व्यापार कर रही है, जहाँ विदेशी तकनीक की कोई जरूरत नहीं है। 80 के देशक में सरकार की ओर से एक नीति बनायी गयी थी। इस नीति के अनुसार 850 ऐसी वस्तुयें हैं, जिसके उत्पादन को लघु उद्योगों के लिये सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जितनी भी विशालकाय बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं, वे सभी इन्हीं उत्पादों के व्यापार में लगी हुयी हैं। लघु उद्योगों के लिये आरक्षित उत्पादों के क्षेत्र में घुसपैठ से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों क्षरा उच्च विदेशी तकनीक लाने की बात एकदम झूठ साबित होती है। देश में व्यापार कर रही कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ के बारे में नीचे तालिका दी जा रही है कि ये कम्पनियाँ 'जीरो तकनीक' के क्षेत्र में व्यापार कर रही हैं अर्थात् ऐसे सामान बना–बेच रही हैं जिनमें विदेशी तकनीक की कोई जरूरत नहीं है। कुछ उदाहरण देखें :–

कम्पनी का नाम	क्या सामान बना/बेच रही हैं
बाटा इण्डिया	जूते, मोजे, रेडीमेड कपड़े, चमड़े के थैले आदि।
बर्जर पेन्ट्स	पेन्ट्स, तरह–तरह के रंग आदि।
ब्रुक बाण्ड इण्डिया लि.	चाय, कॉफी, रसोई घर के मसाले आदि।
कैडबरी इण्डिया लि.	चॉकलेट, बिस्कुट, आईसक्रीम आदि।
कोलफैक्स लेबोरेटरी इ.	शेविंग क्रीम, आफ्टर शेविंग लोशन आदि।
कालगेट–पामोलिव	शेविंग क्रीम
कार्न प्रोडक्ट्स इण्डिया	दही पाउडर, जैली, मक्के के दोन पैक करके बेचना आदि।
क्राम्पटन ग्रीव्ज	घरेलू पंखे, बल्ब, ट्यूब लाइट आदि।
ड्यूफार–इन्टरफैन	सौंदर्य प्रसाधन के सामान, साबुन आदि।
एस.के.एफ. लि.	दर्द निवारक मलहम तथा स्प्रे आदि।
फिस्कर्स इण्डिया	कैंची, चाकू आदि।
फनस्कूल इण्डिया	बच्चों के खिलौने।
जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी	घरेलू पंखे, बल्ब, ट्यूब लाइट, बिजली मोटर आदि।
ज्यौफ्री मैनर्स	टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश, साबुन आदि।
ग्लैक्सो इण्डिया	बेबी फूड, ग्लूकोज के पैक, दवाएं आदि।
गाडफ्रे फिलिप्स	सिगरेट, चाय आदि।
गुडलस नेरोलेक	तरह–तरह के पेन्ट्स।
ग्रामोफोन इण्डिया	रिकार्ड, कैसेट आदि।

गेस्टकीन विलियम	सेफ्टी पिन, बटन, नट–बोल्ट आदि।
हिन्दुस्तान लीवर	साबुन, टुथपेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेन्ट आदि।
सीबा–गायगी	टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर, क्रीम, टूथ ब्रश, दवाएं।
एच.एम.एम. लि.	दूध पाउडर, बालों की क्रीम, बिस्कुट, टॉफी आदि।
आई. सी. आई.	पेन्ट्स तथा रासायनिक रंग आदि।
इन्डिया फोटोग्राफिक कम्पनी	कैमरा, कैमरा–रील आदि।
इन्डियन स्वीइंग मशीन कम्पनी	सिलाई मशीन, रसोई घर के बरतन आदि।
इन्डो–मत्सुशिता कम्पनी	प्रेशर कुकर, घरेलू बरतन आदि।
ऑयन एक्सचेंज इण्डिया	वाटर फिल्टर्स।
आई. टी. सी.	सिगरेट, होटल व्यवसाय, वनस्पति तेल आदि।
जे. एल. मॉरीसन	टूथपेस्ट, दूध की बोतल, फेस क्रीम।
जे. के. हेलन क्रूटिस	सौंदर्य प्रसाधन के सामान।
जॉनसन एण्ड जॉनसन	साबुन, टेल्कम पाउडर, सेनेटरी नेपकिन्स, बड्स।
किसान प्रॉडक्ट लि.	जैम, स्क्वैश, बिस्कुट, चटनी आदि।
कोठारी जनरल फूड्स	कॉफी, साफ्ट ड्रिंक, पान मसाला आदि।
लखनपाल नेशनल	ड्राई सैल।
लिप्टन इण्डिया लि.	चाय, साफ्ट ड्रिंक, वनस्पति तेल।
मदुरा कोट्स	धागे (सिलाई के लिये)।
मेटल बाक्स	प्लास्टिक के बर्तन आदि।
बास्किन राबिन्स	आईसक्रीम
नेस्ले इण्डिया	साबुन, टेल्कम पाउडर, कोल्ड क्रीम
प्राक्टर एण्ड गैम्बिल	बाम, टॉफी, साबुन, चॉकलेट आदि।
रेकिट एण्ड कोलमैन	बूट पॉलिश, साबुन, डिटर्जेन्ट, लोशन आदि।
विमको लिमिटेड	माचिस (दियासलाई), नमक आदि।
कोका कोला	साफ्ट ड्रिंक
लोटस चॉकलेट्स	बच्चों की चॉकलेट, बिस्कुट आदि।
रिगले	चॉकलेट, टॉफी आदि।
रफेम इण्डिया	चॉकलेट, टॉफी, लैमनचूस
यार्डल	सौंदर्य प्रसाधन और साबुन
बाकारोज परफ्यूम्स	सुगंधित सेन्ट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन
लेबोरेटरीज गार्नियर	साबुन, सौंदर्य प्रसाधन के सामान
रीबुक इण्डिया	जूते, चप्पल आदि।
जिलेट इण्डिया	सेफ्टी रेजर, ब्लेड आदि।
विल्टेक इण्डिया	सेफ्टी रेजर, ब्लेड आदि।
स्टीफेन केमीकल्स	डिटर्जेन्ट पाउडर, साबुन आदि।

विदेश से आयी टेक्नोलॉजी (?)

दुनिया के विकसित–अमीर देशों के द्वारा दी गयी टेक्नोलाजी के बदले प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रूपया रायल्टी के रूप में हमारे देश से बाहर जा रहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि इन विकसित देशों द्वारा हमारे देश को कौन सी टेक्नोलाजी दी गयी है ? किस देश ने किस प्रकार की टेक्नालोजी दी है, इसके कुछ उदाहरण :

टेक्नोलॉजी	कहाँ से आयी
नमक	स्विट्ज़रलैण्ड
बच्चों के कपड़े	नीदरलैण्ड
केले की चटनी	डेनमार्क
चाकलेट–टाफी	ब्रिटेन
साफ्ट ड्रिंक	अमरीका
चीनी–मट्टी के बर्तन	जापान, इटली, स्वीडन
कांच का सामान	अमरीका, बेल्जियम
बाल प्वाइंट पेन व रिफिल	स्विटजरलैण्ड, जर्मनी, जापान,
	अमरीका, फ्रांस
छाता	जापान, ताईवान
प्लास्टिक के बर्तन	ब्रिटेन
स्कूल बैग	ब्रिटेन
मोटरकार की सीट	जापान
गहने–जेवरात	कनाडा
सुई	स्विट्ज़रलैण्ड
प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे व	
अन्य सामान	ब्रिटेन, अमरीका
खिलौने बनाने के लिए	अमरीका, जापान, इटली,
	कोरिया, हांगकांग
स्पोर्ट्स कैप	कनाडा
च्यूइंगम और बबलगम	दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन
आलू–चिप्स	अमरीका
टमाटर की चटनी	बुल्गारिया, अमरीका
घरेलू चाकू	नीदरलैण्ड
प्लास्टिक के फूल	अमरीका
सौन्दर्य प्रसाधन	अमरीका, फ्रांस
गैस लाइटर	स्पेन

कैंची	फिनलैण्ड
फास्ट–फूड	नीदरलैण्ड, अमरीका, स्विट्जरलैण्ड
ताकिया	फ्रांस
हैण्ड बैग	अमरीका
लिपिस्टिक	अमरीका
बालों के शैम्पू एवं आफ्टर	
शेव लोशन	फ्रांस, अमरीका, ब्रिटेन, नीदरलैण्ड

माल देशी, मुहर विदेशी

कई बार ऐसा भी होता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ न तो पूँजी लाती है और न ही कोई उच्च तकनीक। होता यह है कि ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कुछ भारतीय कम्पनियों के साथ 'फ्रेंचाइज एग्रीमेन्ट' करती हैं या 'सब कान्ट्रेक्टिंग एग्रीमेन्ट' करती हैं। इसके तहत उत्पादन का काम तो वह भारतीय कम्पनी करती है लेकिन उत्पादित माल पर नाम बहुराष्ट्रीय कम्पनी का ही होता है। अर्थात् बाजार में बिकने वाले माल की उत्पादक कोई स्वदेशी कम्पनी है लेकिन माल विदेशी कम्पनी के नाम से बिकता है। पूँजी लगाये स्वदेशी कम्पनी, तकनीक इस्तेमाल करे स्वदेशी कम्पनी, उत्पादन कराये स्वदेशी कम्पनी, लेकिन माल बिके विदेशी कम्पनी के नाम पर। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का यह गोरखधंधा इस देश में खूब चल रहा है।

नीचे ऐसी कम्पनियों की सूची दी जा रही है जिन्होंने न तो पूंजी लगाई, न कोई टेक्नोलॉजी लाये हैं और न ही कोई फैक्टरी लगाई है लेकिन माल उनके नाम से बि रहा है और करोड़ों रूपये देश से बाहर जा रहा है।

सामान का नाम	भारतीय उत्पादक कम्पनी	बेचने वाली बहुराष्ट्रीय
जूते	आगरा, कानपुर, कलकत्ता, अन्य स्थानों से मोचियों द्वारा ठेके पर	बाटा (इण्डिया) लि.
कोलगेट टूथ पाउडर	क्रिस्टल कॉस्मेटिक्स, हैदराबाद	कोलगेट–पामोलिव इण्डिया
चार्मिस लोशन	एम.जी.साहनी एण्ड कम्पनी, दिल्ली	कोलगेट–पामोलिव इण्डिया
हेलो शैम्पू	एम.जी.साहनी एण्ड कम्पनी, दिल्ली	कोलगेट–पामोलिव इण्डिया
पामोलिव शैम्पू	एम.जी.साहनी एण्ड कम्पनी, दिल्ली	कोलगेट–पामोलिव इण्डिया

कोलगेट टूथपेस्ट	सन शाइन कॉस्मेटिक्स	कोलगेट–पामोलिव इण्डिया
कोलगेट ब्रश	अडवानी इण्डस्ट्रीज, महाराष्ट्र	कोलगेट–पामोलिव इण्डिया
आयोडेक्स (बर्न स्प्रे)	अक्रा पैक इंडिया	एस्केफ इण्डिया लि.
सिबाका टूथ पाउडर	कैन्ट लैब्स, बम्बई	हिन्दुस्तान सीबा–गायगी लि.
सिग्रल टूथ पेस्ट	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट्स	हिन्दुस्तान लीवर लि.
लिरिल फ्रेशनेश टेल्कम	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट्स	हिन्दुस्तान लीवर लि.
क्लीनिक शैम्पू	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट्स	हिन्दुस्तान लीवर लि.
सनसिल्क शैम्पू	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट्स	हिन्दुस्तान लीवर लि.
फेयर एण्ड लवल क्रीम	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट्स	हिन्दुस्तान लीवर लि.
टियारा शैम्पू	फियोरा कॉस्मेटिक्स	जे.के. हेलन करटिस लि.
निविया आफ्टरशेवलोशन	कॉस्मोपैक सिल्वासा	जे.एल.मॉरीसन एण्ड जॉन्स लि.
निविया टेल्कम	केवन कॉस्मेटिक्स	जे.एल.मॉरीसन एण्ड जॉन्स लि.
निविया क्रीम	केवन कॉस्मेटिक्स	जे.एल.मॉरीसन एण्ड जॉन्स लि.
क्यूटीकुरा टेल्कम	नीनन प्रॉडक्टूस	म्यूलर इण्डिया लि.
पामेड वैसलीन	जे. बी. अडवानी एण्ड कं.	पाण्ड्स इण्डिया लि.
पाण्ड्स सण्डल टेल्कम	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट	पाण्ड्स इण्डिया लि.

घटते रोजगार और बढ़ती बेरोजगारी

आँखे मूंदकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से, जब हम बनी–बनायी तकनीक का आयात करते है तो हम दरअसल दूसरे देशों के इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों को काम मुहैया कराते हैं। अर्थात् अपने देश से विकसित देशों को रोजगार का निर्यात करते है। इस तकनीकी आयात की प्रक्रिया में भारतीय इंजीनियरों व तकनीकी विशेषज्ञों को जो अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता था और अधिक रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकते थे, वे एकदम समाप्त हो जाते हैं। इससे हमारे देश के इंजीनियर व तकनीकी विशेषज्ञ बेकार रहते है, वही दूसरी ओर किसी विकसित औद्योगिक, देश को जहाँ की कम्पनी होती है, अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा जब बनी बनायी तकनीक का आयात होता है तो भारतीय इंजीनियरों का कार्य सिर्फ तन्त्र को चालू रखने का होता है। सर्वविदित है कि कारखानों के रख–रखाव के लिये किसी बड़ी प्रतिभा की जरूरत नहीं होती है। जबकि तकनीकी विशेषज्ञता का योगदान नयी विधियाँ विकसित करने में और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान द्वारा विकास करने में होता है। इस प्रकार जो इंजीनियर या तकनीकी विशेषज्ञ देश में काम में लगे हूये हैं, उनकी प्रतिभा का भी सही उपयोग नहीं हो पाता है।

औद्योगिक देशों को एक और बड़ा लाभ उस बुद्धि शक्ति के आयात से मिलता है जो सुनहरे भविष्य की खोज में भारत जैसे देशों से उनके यहाँ जाती है। प्रौद्योगिकी विज्ञान तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों में विशेष शिक्षा पाकर जो लोग देश को उसका कुछ भी लाभ दिये बगैर ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी इत्यादि चले जाते हैं वे उन देशों को न सिर्फ आर्थिक व बौद्धिक लाभ पहुँचाते हैं बल्कि ऐतिहासिक लाभ भी।

'सेंटर फार प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन' (नयी दिल्ली) के अध्ययन के मुताबिक प्रतिभा पलायन के कारण भारत को अब तक 13 अरब (247 अरब रूपये लगभग) का नुकसान हो चुका है और अगर यह नही रूका तो शताब्दी के अंत तक 5 लाख से ज्यादा कुशल और प्रशिक्षित भारतीय विदेशों में काम कर रहे होंगे। फिलहाल 4 लाख 10 हजार भारतीय विदेशों में काम कर रहे है। अध्ययन के अनुसार भारतीय इंजीनियर विदेशी में 32 प्रतिशत, डॉक्टर 28 प्रतिशत और वैज्ञानिक 5 प्रतिशत है।

जब एक डॉक्टर भारत को छोड़कर अमेरिका जाता है तो देश को 3०5 करोड़ रूपये का नुकसान होता है लेकिन वह अमरीका में 60 करोड़ यानि 20 गुना धन कमा कर उस देश की समृद्धि में भागीदार होता है। जबकि दूसरी ओर भारत एक विकासशील देश है जहाँ डॉक्टरों का अभाव है, जहाँ शहर में 5 हजार लोगों पर एक डॉक्टर है तथा गाँव में 45 हजार लोगों पर एक डॉक्टर है।

भारत से निकलने वाली प्रतिभाओं की एक बड़ी संख्या अमेरिका चली जाती है। 1957 से 1965 तक अमेरिका में भारतीय वैज्ञानिकों, डॉक्टरों तथा इंजीनियरों की संख्या सिर्फ 1000 थीं वही 1966 से 1968 तक वह संख्या 4000 हो गयी। 1977 तक भारत में 16,849 वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर अमेरिका चले गये।

उदार आर्थिक नीतियों के चलते देश में विदेशी अनुबंधों की बाढ़ आ गयी है। जुलाई 1995 तक देश में 20,000 से अधिक विदेशी अनुबंध चल रहे हैं। जिनके चलते गैर जरूरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास ज्यादा हुआ है। पिछले 5 वर्षों में संगठित क्षेत्रों (बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ व निजी देशी कम्पनियाँ) में सबसे अधिक विकास हुआ है जबकि इस क्षेत्र में रोजगार अवसरों की वृद्धि दर मात्र 1.5 प्रतिशत रही है। यानि संगठित क्षेत्र में पूँजी निवेश सबसे अधिक हुआ है लेकिन रोजगार के अवसर उस तुलना में पैदा नहीं हुये।

दूसरी ओर देश का लघु उद्योग का क्षेत्र है जिसमें सबसे कम पूँजी का निवेश किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश के जितने भी रोजगार है उनमें से 80 प्रतिशत इन असंगठित लघु उद्योगों में है। लघु उद्योगों में 1986–87 में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 10.1 करोड़ थी जो वर्ष 1987–88 में बढ़कर 10.7 करोड़ तक पहुँच गयी भारत में 1988 के अन्त तक लघु उद्योगों की कुल संख्या 14.6 लाख थी। इसमें से 3 लाख लघु इकाईयाँ इन विशालकाय कम्पनियों के बाजार में एकाधिकार के चलते बीमार हो गयी हैं और बन्द होने के कगार पर हैं।

चूँकि इन विदेशी कम्पनियों ने लघु उद्योग में बनने वाले हर सामान को बनाने के क्षेत्र में घुसपैठ कर रखी है, अतः लगभग 10 लाख 30 हजार अन्य छोटी इकाईयाँ इनके सामने प्रतिस्पर्धा में धीरे–धीरे चल रही है। हर वर्ष देश में बीमार इकाईयों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जिससे लाखों लोग बेराजगार होते जा रहे हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 84 लाख नये बेराजगार लोग पैदा हो जाते है। इनमें से अधिकांश छोटी इकाईयों के बन्द हो जाने की वजह से बेरोजगार हो जाते है।

इसके अतिरिक्त इन विदेशी कम्पनियों ने विकास के नाम पर सैकड़ों वर्षो से चल रहे हमारे देशी कारोबार, हुनर और हस्त शिल्प को रौंदा है, जिसमें लगे करोड़ों लोगों की रोजी–रोटी छिन गयी है। आधुनिकीकरण की सबसे ज्यादा मार पड़ी है कारीगरों, दसतकारों व कुटीर उद्योगों पर। जूता उद्योग का आधुनिकीकरण होगा तो कोन मारा जायेगा ? मोची। कपड़ा उद्योग का मशीनीकरण होगा तो कौन बरबाद होगा ? बुनकर। वस्त्र उद्योग का रेडीमेडीकरण (सिले सिलाये कपड़े) होगा तो कौन नष्ट होगा ? दर्जी। मिठाई बनाने के क्षेत्र में जब विदेशी कम्पनियाँ घुसेंगी तो कौन हैरान होगा ? हलवाई। कुल्हड़ की जगह विदेशी कम्पनियाँ प्लास्टिक के गिास बनाने लगेंगी तो कुम्हार किस काम का रह जायेगा ? फलों का रस डिब्बा बन्द करके बेचने के लिये विदेशी कम्पनियाँ आयेंगी तो कौन समाप्त होगा ? फलों का रस बेचने वाले लोग। पानी बेचने के लिये भी विदेशी कम्पनियाँ आयेंगी तो आगे कहा नहीं जा सकता, हम लोग स्वयं सोच लें।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार सन् 1994 के अन्त तक देश में कुल बेरोजगारी की संख्या लगभग 16 करोड़ है। यह संख्या उन लोगों की है जिन्होंने अपना पंजीकरण सरकार कार्यालयों में करवा लिया है। इसके अतिरिक्त देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कभी इस तरह का पंजीकरण करवाने के लिये प्रस्तुत नहीं होते है। गाँव के अधिकांश युवक तो पंजीकरण करवाते ही नहीं है। इस तरह के लोगों को मिलाकर अनुमानित बेरोजगारों की संख्या 20 करोड़ से अधिक है।

एडीडास (Adidas), प्यूमा (Puma), ड्यूक (Duke), नाईक (Nike), लाट्टो (Lotto), आदि विदेशी कम्पनियों के भारत में सिले हुये (रेडीमेड) कपड़ों के क्षेत्र में घुस जाने से देश भर के लाखों दर्जियों की आजीविका छिनेगी। भारत में बहुत तेजी से सिले हुये कपड़ों का बाजार बनता जा रहा है।

एडीडास, प्यूमा, लोट्टो द्वारा भारत के खेल सामान बनाने वाले क्षेत्र में घुस जाने से, जालन्धर के खेल सामान उत्पादन के लघु उद्योग में लगे हुये 60 हजार कुशल कारीगरों के अस्तित्व को खतरा है। इसके अलावा उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा दिल्ली में लगे हुये लगभग 1 लाख 80 हजार अन्य कुशल श्रमिकों का रोजगार भी खतरे में पड़ जायेगा।

ब्रिटानिया के चलते उ.प्र., बिहार, व मध्यप्रदेश के बेकरी उद्योग में लगे 1 लाख 22 हजार से भी अधिक श्रमिकों की रोजी–रोटी चौपट होने के कगार पर है।

बाटा व प्लास्टिक के जूतों के चलने से देश के लाखों मोचियों को बरबाद किया है। विमको ने बरेली व शिवाकाशी के माचिस उद्योग में लगे हजारों श्रमिकों को चौपट कर दिया है। पेप्सी कोला के आने से खाद्य सामग्री और पेय बनाने वाली देश की 2525 छोटी इकाइयों में से अधिकांश बंद हो गयी। लगभग 3 लाख 75 हजार कुशल कारीगर श्रमिक अपनी आजीविका के लिए दर–दर भटक रहे है।

गुलाम होती खेती

आजकल देश में एक नारा बहुत जोर शोर से इन कम्पनियों द्वारा दिया जा रहा है कि 'खेती को उद्योग बनाओ'। यानि अब खेत को कारखाना बनाने की साजिश देश में चल रही है। अब ये कम्पनियाँ खेती के बल पर और अधिक मालामाल होने के सपने देख रही है। हमें याद होना चाहिए कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले इन्ही कम्पनियों द्वारा देश में 'हरित क्रान्ति' का नारा दिया गया था। खेती की उन्नति और विकास के नाम पर चले इस नारे ने भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था और उसके साथ जुड़ी हुयी, समाज व्यवस्था को चौपट करके रख दिया। उसी तरह अब खेती की उन्नति के नाम पर खेती को उद्योग का दर्जा देने की बात भारत के सामान्य और बहुसंख्यक किसानों के लिये देश की बची खुची कृषि व्यवस्था के लिये घातक सिद्ध होगी।

इन कम्पनियों द्वरा निरंतर यह प्रचारित किया जा रहा है कि खेती में विदेशी पूँजी निवेश की अत्यधिक जरूरत है। जिसके बिना अब खेती का विकास नहीं हो सकता है। यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। वास्तव में खेती स्वयं ऐ ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें से पूँजी का निर्माण होता है, हरित क्रान्ति की नारे बाजी से खेती को ऐसी दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति में ला दिया गया है कि खेती को पूँजी की जरूरत हो। आज खेती को उद्योग बनाने की बात कहकर इस बात की कोशिश की जा रही है कि खेती का रोजमर्रा का सामान्य काम भी बिना पूँजी के न चल सके।

खेती के लिये मुख्य तौर से दो ही चीजें आवश्यक होती है– एक किसान की मेहनत और पशु की मेहनत; दूसरे धरतीख बीज, खाद, पानी आदि प्राकृतिक साधन। ये दोनों ही चीजें ऐसी है जो कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार खेती एक सम्पूर्ण स्वावलंबी धंधा है।

किसान एक बीज बोता है लेकिन इस बीज में से जो भी दाने प्राप्त होते है, उनमें से हर एक दाना फिर बीज का काम करता है। इस प्रकार खेती एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें लगाये हुये मूल का कई सौ गुना प्रतिफल मिलता है और जिसमें से बचत हो सकती है और बचत से ही पूँजी बनती है। कारखाना किसी भी चीज का हो, न तो उसमें चीज सचमुच पैदा होती है, न ही उसका गुणाकार होता है। कारखाने में केवल कच्चे माल का रूपांतर होता है, नया उत्पाद नहीं। कारखानों में जिस कच्चे माल से चीजें तैयार होती है, वह कच्चा माल भी अधिकतर खेती से ही प्राप्त होता है।

यह एक विडंबना ही है कि वास्तव में उत्पादन और पूँजी का निर्माण करने वाला किसान खाद, बीज और कीटनाशकों के लिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गुलाम बन गया है। अपनी मेहनत जे खुद उसके पास है तथा प्राकृतिक तत्व जो सब जगह उपलब्ध है इन दोनो के संयोग से खुद उत्पादन करने वाले किसान को आज भिखारी बनाकर रख दयिा है इन विदेशी कम्पनियों ने। वास्तव में खेती कोई धंधा नहीं है वह जीवन जीने की प्रक्रिया है। जो खेती को धंधा बनाना चाहते है, उनका उद्‌देश्य है कि जीवन जीने की इस स्वावलंबी शैली को परावलंबी बना दिया जाय ताकि किसान का और खेती का शोषण किया जा सके। स्वावलंबी समाज में

लोग अपनी मेहनत पर जीने वाले होते है, दूसरे के शोषण पर नहीं। खेती को उद्योग का दर्जा देने का मतलब है किसान को गुलाम बनाना। जब खेती को उद्योग की तरह चलाया जायेगा तो अधिक अन्न उपजाने के लिये बीज, खाद, कीटनाशक दवायें और पानी खरीदने के लिये किसान को और अधिक बाध्य कर दिया जायेगा। इसके लिये उसे कर्जा दिया जायेगा। फिर उस कर्ज की अदायगी में उसकी फसल उससे ले ली जायेगी। इस प्रकार वह पूरी तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व बाजार का बंधुआ मजदूर बन जायेगा। बड़े–बड़े फार्म बनेंगे तो जमीन छोटे किसानों से खरीदी जायेगी। इस तरह जमीन का मालिक धीरे–धीरे इन कम्पनियों की कृपा से जमीन पर काम करने वाला मजदूर बन जायेगा; फिर वह किसान नही रहेगा।

बीज का धंधा

पश्चिम के देशों ने विकास की अपनी अवधारण को दुनिया के कमजोर देशों पर लादा है। विकास एक नये प्रकार की गुलामी का मन्त्र बन गया है। हरित क्रान्ति इस प्रकार के विकास का एक बेशर्म उदाहरण है। इस तथाकथित क्रान्ति की शुरूआत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ऐसे बीज तैयार करने के साथ हुई जिनसे उपज बढ़ जाती है। अतः ऐसे संकर बीजों का उत्पादन इन विदेशी कम्पनियों ने करना शुरू किया। इस बीज की दो प्रमुख विशेषतायें होती हैं जो विदेशी कम्पनियों के लिये अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुयीं। पहली विशेषता यह है कि इस संकर बीज से अधिक उपज प्राप्त करने के लिये भारी मात्रा में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता होती है। इन बीजों से पैदा होने वाली फसलों पर कीड़ा भी बहुत जल्दी और अधिक लगता है। जब अधिक रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता हुयी तो इन कंपनियों ने खाद व दवाओं को बनाकर बेचना शुरू किया और हरित क्रान्ति के दौरान अकूत मुनाफा बटोरा।

इस संकर बीज की दूसरी विशेषता यह है कि सिर्फ एक बार ही फलता है। इस बीज से जो दाने पकते हैं, वे पुनः बीज का काम नहीं देते है, इसलिये किसान को हर साल नया बीज खरीदना पड़ता है। अतः जैसे–जैसे संकर बीज का चलन बढ़ता गया वैसे–वैसे बीज का बाजार विदेशी कम्पनियों के लिये पैदा होता गया। भारत में एक वर्ष में (सन् 1987 में) इन कम्पनियों ने जो बीज बिक्री किए है उसका आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है :–

विदेशी कम्पनी का नाम	**बीज की बिक्री**
पायोनियर (Pioneer)	169.26 करोड़ रुपये
शेल (Shell)	66.50 करोड़ रुपय
सैन्डोज (Soondoz)	54.91 करोड़ रुपय
फाइजर (Pfizer)	28.19 करोड़ रुपय
अपजोन (Upjohn)	38.00 करोड़ रुपय
आई. सी. आई. (I.C.I)	30.40 करोड़ रुपय
लीमाग्रेन (Limagrain)	32.49 करोड़ रुपय

सीबा–गायगी (Ciba Geiga) 28.88 करोड़ रुपय
लाफार्ज (Lofarge) 28.50 करोड़ रुपय
वोल्वो (Volvo) 26.60 करोड़ रुपय

बीज के बाजर में इन विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ भी किसानों को लूट रही है। किस विदेशी कम्पनी के पास बीज बेचने वाली अपनी और कितनी कम्पनियाँ है, इसका आंकड़ा नीचे प्रस्तुत है :–

कम्पनी का नाम		नियन्त्रण में अन्य बीज कम्पनियों की संख्या
शेल	(Shell)	68
सैन्डोज	(Sandoz)	37
फाइजर	(Pfizer)	34
सीबा–गायगी	(Ciba Geiga)	26
अपजोन	(Upjohn)	15
केमानोबेल	(Kamanobel)	11
आक्सीडेंटल पेट्रोलियम	(Occidently Petrolium)	10

इसके अतिरिक्त 16 सितम्बर 1988 को सरकार द्वारा घोषित 'नयी बीज–नीति' के तहत कुछ और विशालकाय विदेशी कम्पनियों ने बीज का व्यापार शुरू कर दिया है। वे कम्पनियाँ निम्न है :–

1. कारगिल सीड कार्पोरेशन (Cargil Seeds Corporation)
2. पी. एच. आई. बायोजीन लिमिटेड (P. H. I. Biogene ltd.)
3. नेशनल आर्गेनिक लि. (Beio Sheetal Seeds Company)
4. बेजो शीतल सीड कम्पनी (Beio Sheetal Seed Company)
5. आई. टी. सी. (Indian Tobaco Company)
6. हिन्दुस्तान लीवर (Hindustan Lever)

कीटनाशकों का कहर

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रायपुरा–जंगला गांव में 15 अप्रैल 1990 की रात को एक समारोह में विषाक्त भोजन खाने से 200 से अधिक लोग मारे गये। इस दर्दनाक हादसे के कारणों का सही–सही पता चला; जब पूरी जांच की गयी। जांच के बाद पाया गया कि लोगों की मोत अत्यन्तक घातक कीटनाशक पैरथियान और ई.एन.पी. के कारण हुयी। जिस गेहूं की बनी पूडियाँ इस भोज में खायी गयी उस गेहूं में ये दोनों कीटनाशक मिले हुये थे। उल्लेखनीय

है कि इन दोनों कीटनाशकों पर सभी पश्चिमी देशों में रोक लगी हुयी है। ये दोनों कीटनाशक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी प्रतिबन्धित है। मगर हमारे देश में ये दोनों ही कीटनाशक इन विदेशी कम्पनियों द्वारा बनाये जा रहे है और धड़ल्ले से बि रहे है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जाल में फंसकर यह माना गया कि खेती की उपज बढ़ाने के लिये यदि ढेरों तरह के जहरीले कीटनाशी रसायनों का भरपूर इस्तेमाल जारी नहीं रहा तो कीटाणु सारी फसल को चट कर जायेंगे और सारी मानवता भुखमरी की चपेट में आ जायेगी। इन कम्पनियों द्वारा प्रचारित विकास; किसी अन्य विकल्प को प्रकृति प्रेमियों व पर्यावरणवादियों का सुहाना सपना समझकर उसकी खिल्ली उड़ाता है। मिट्‌टी की हिफाजत का परम्परागत देशी तौरतरीका, खरपतवार, घरेलू व कृषीय कूड़ा–कचरा और जानवरों के मल–मूत्र से बनी खाद, परस्पर मदद पहुँचाने वाली फसलों का बारी–बारी से बोया जाना यानी फसल–चक्र, यह सब विदेशी कम्पनियों, द्वारा विकसित तकनीक ने लील लिया है। मिट्‌टी, हवा, पानी और फसल के बीच जो प्राणवान, समन्वित और निरापद नाता था, वह बेमानी हो गया है। उसक स्थान ले लिये बेकस मिट्‌टी और जहरीले रासायनिक द्रव्यों ने।

'हरित क्रान्ति' के बाद खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर पूरी तरह निर्भर होकर रह गयी है। इसका नतीजा यह है कि जो अनाज जीवनदायी माना जाता है, वही उर्वरकों व कीटनाशकों के कारण गुणवत्ता में निम्न स्तर का होकर अस्वास्थ्यकर और जानलेवा तक होने लगा है। 'हरित क्रान्ति' के दौरान अनाज उत्पादन में चमत्कारिक वृद्धि असल में एक मिथक है, उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार सन् 1947 के बाद के पहले दशक में जहाँ अन्न उत्पादन में 3.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुयी। वहीं अगले दशक में अर्थात् 60 के दशक में यह दर मात्र 2.25% प्रतिशत रही। यह दर दो दशकों तक जारी रही। एकमात्र गेहूं ही ऐसा अनाज है जिसका उत्पादन 4.5% वार्षिक दर से बढ़कर 7.62% हो गयी लेकिन दूसरी ओर का सच यह है कि बाकी अन्य सभी अनाजों की वृद्धि दर लगातार घटती गयी। इन आँकड़ों से हरित क्रान्ति के भोजन पर पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते है। हरित क्रान्ति के दौरान गेहूं का उत्पादन क्षेत्र बढ़ता गया और मोटे अनाजों, दालों, तिलहन आदि का उत्पादन क्षेत्र घटता गया। इस कारण भोजन में प्रोटीन की मात्रा घटती गयी। नये अनाजों का असर पशुओं को भी झेलना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा उपज देने वाली फसलों का भूसा पोषक तत्वों के मामले में कमजोर होता है।

आज अनाज, फल, सब्जियाँ, दलहन, तिलहन, दूध और मांस–मछली तक सभी में विषाक्त तत्वों की भरमार है जो एक धीमी मौत की ओर हमें धकेल रही है। इसके बावजूद रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल न केवल जारी है बल्कि तेजी से बढ़ भी रहा है। आँकडों पर नजर डालें तो विशेषज्ञों का कहना है कि सन् 1960 से 1980 के दोरान भारत में कीटनाशकों की खपत में 20 गुना इजाफा हुआ है। इस दौरान कीटनाशकों के उत्पादन में 14% की बढ़ोत्तरी हुयी है और इनका आयात भी इस बीच 7 गुना बढ़ा।

सन् 1989 से 1990 के बीच में कीटनाशकों की खपत 1 लाख 20 हजार टन हुयी। इसमात्रा का दो तिहाई भाग खेती में इस्तेमाल हुआ। एक अनुमान के अनुसार पिछले 20 वर्षो में कीटनाशकों के इस्तेमाल से 10% फसल को बचा लिया गया। लेकिन जिस अनुपात में इन

कीटनाशकों का जहर भोजन के जरिये देशवासियों के शरीर में पहुँचा है और उससे जो हानि हुयी व हो रही है, उसे देखते हुये 10% फसल को बरबाद होने से बचाने की उपलब्धि बहुत महंगी है। जन और धन की इस व्यापक हानि के सामने 10% फसल की बरबादी का जोखिम सस्ता ही ठहरेगा।

इन कीटनाशकों के कारण देश में कितने लोग काल–कवलित हुये है, इसके सही–सही आँकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है। कीटनाशक मिले भोजन व असावधानीवश कीटनाशकों के सम्पर्क में आने के कारण जहाँ हजारों लोग मौत के मुंह में समाये हैं वहीं इन कीटनाशकों से पैदा होने वाली बीमारियाँ भी आम होती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत तीसरे नंबर पर है जहाँ कीटनाशक हादसे ज्यादा और हर साल होते है। इन कीटनाशकों से जोड़कर उनकी शिनाख्त करना बहुत लंबी प्रक्रिया है।

कीटनाशकों से जुड़ा एक पहलू यह भी है कि भारत जैसे विकासशील देश में इस्तेमाल होने वाले 70% कीटनाशक ऐसे हैं जिन पर विकसित देशों में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। डी.डी.टी. हमारे देश्ज्ञ में एक आम कीटनाशक है पर अन्य अनेक देशों में यह प्रतिबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जमीन, वनस्पति और शरीर पर इसका बहुत लंबे समय तक घातक असर बना रहता हैं मगर अपने देश में कृषि क्षेत्रों में इसकी खपत 3500 टन प्रतिवर्ष तथा मलेरिया उन्मूलन आदि कार्यक्रमों में 4000 टन प्रतिवर्ष है। बी.एच.सी. (बेंजीन हेक्साक्लोराइड), मिथाइल पैराथियान, हैप्टाक्लोर, डाई ब्रोमोक्लोरो प्रोपेन, एजेंट आरेंज, फास्वेल, डेल्ड्रिन, क्लोरेडेन, बूटाक्लोर जैसे कीटनाशक जो पश्चिमी देशों सहित दुनिया के कई अन्य देशों में प्रतिबन्धित हैं, जिनका बेचना उन देशों में गंभीर अपराध घोषित हो चुका है, उन्हीं कीटनाशकों के घातक असर का अहसास करने के लिये इन 'हरित क्रान्ति' के झंडाबरदारों को कितनी भोपाल त्रासदियों का इंतजार है।

आधुनिक विकास या प्रकृति विनाश

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कारगुजारियों और उसके फलस्वरूप विकसित विकास–प्रक्रिया का सबसे भयावह नतीजा प्रकृति के विनाश के रूप में हुआ है। पर्यावरण की बरबादी का मुख्य कारण है।, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की उत्पादन शैली, जिसके चलते पश्चिम के देश अमीर हुये हैं। लेकिन अब यह संकट उन देशों पर सबसे अधिक मंडरा रहा है जहां से आधुनिक विकास प्रक्रिया की शुरूआत हुयी थी। पश्चिम के देशों में जितनी उपभोग की वस्तुयें बन रही हैं, उतनी ही अधिक उपभोक्ताओं की हवस बढ़ रही है। नतीजा उस कचरे के रूप में सामने है जो हमारी पृथ्वी को दिन–दूनी रात–चौगुनी गति से प्रदूषित करता जा रहा है जो अपने आने वाले दिनों में कई तटीय शहरों को विश्व के नक्शे से समाप्त कर देगा।

वर्तमान में कार्बन डाईआक्साइड पयावरण के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। उद्योगों के इस अंधे युग के आरंभ होने से पहले कार्बन डार्ठआक्साइड वातावरण में एक निश्चित अनुपात में रहती ि। एकसर्वेक्षण के अनुसार औद्योगिक क्रान्ति से पहले वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड प्रति 10 लाख अंशों में 280 अंश थी। आज इसमें 25 प्रतिशत बढोत्तरी हो चुकी है और सन् 2075 तक गैस की मात्रा दुगुनी हो जायेगी। अगर इस बात को दुनिया भर के देशों के जंगलों के विनाश से जोड़ दिया जाए, तो यह अंदाज सामने आता है कि कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा वायुमंडल में आज से मात्र 40 वर्ष बाद दुगुनी हो जायेगी। इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गये हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। पिछले 110 साल की तुलना में इस दशक के पहले 8 सालों में ही 4 साल सबसे गर्म साल थे। 1988 के पहले 7 महिनों ने तो एक शताब्दी का रिकार्ड तोड़ दिया, ये 7 महिने इतने अधिक गर्म थे। 23 जून 1988 दोपहर में जब अमरीकी शहरों में 38 डिग्री सेल्यिस से ज्यादा गर्मी थी, हजारों किलोमीटर उपजाऊ भूमि पर पहली बार भयंकर सूखा पड़ा था और जो अंधड़ चल रहे थे वैसे इस शताब्दी में कभी देखने को नहीं मिले।

सन् 1950 से लेकर 1986 के बीच किस देश ने वातावरण में कितनी कार्बन डाईआक्साइड गैस छोड़ी इसका आँकड़ा नीचे दिया जा रहा है।

देश का नाम	**कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा**
उत्तरी अमेरिका	40.2 अरब टन
पूर्वी यूरोप के देश	31.9 अरब टन
पश्चिमी यूरोप के देश	25.1 अरब टन
एशिया महाद्वीप के सभी देश	9.3 अरब टन
प्रशांत क्षेत्र के सभी देश	7.2 अरब टन
अफ्रीका के देश	14.43 अरब टन

वैज्ञानिक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी की जलवायु को बदलना शुरू कर दिया है। 'ग्रीन हाउस' ऐसे विशाल कमरे होते हैं जहाँ खास किस्म के पौधे उगाये जाते हैं, विकास के तथाकथित ढाँचे के अन्तर्गत चलने वाले उद्योगों से कार्बन डाईआक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आक्साइड, ओाजेन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन तथा कई अन्य गैसें वायु मंडल के निचले हिस्से में जमा हो जाती हैं। जिसके कारण पृथ्वी की गरमी को ये गैसे ऊपर जाने से रोकती हैं जिससे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। ताकि पौधों पर बदलते हुये मौसम का असर न पड़े। इन कमरों में अनुकूल मौसम बनाया जाता है। शीशे की छतें इन कमरों में लगी रहती हैं जिनसे धूप तो मिलती ही है लेकिन अन्दर गर्मी एक निश्चिम नाप से ज्यादा नहीं होती है। इन ग्रीन हाऊस का सबसे बड़ा असर यह होता है कि जो कार्बन डाईआक्साइड गैस बनती है वह कमरे से बाहर नहीं जाती जिससे तापमान बढ़ जाता है क्योंकि कार्बन डाईआक्साइड में गर्मी सोखने की विलक्षण क्षमता है, इसी वजह से ग्रीन हाऊस ठंडे मौसम में भी गर्म रहता है। अतः पृथ्वी पर भी यही प्रक्रिया दोहरायी जाती है कि कार्बन डाईआक्साइड या ऐसी ही अन्य गैसें गर्मी को पृथ्वी से बाहर जाने से रोकती हैं तो इसे वैज्ञानिकों ने 'ग्रीन हाउस प्रभाव' का भोला सा नाम दिया है।

'ग्रीन हाउस प्रभाव' के कारण पृथ्वी की जलवायु का ताप स्थायी रूप से कुछ डिग्री बढ़ जाने से प्रलय का कहर ढा सकता है। इसके कारण मौसम बदल सकता है, उपजाऊ क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है, रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश हो सकती है, पर्वतों पर पिघलते हुये हिमनद समुद्र की सतह को दो मीटर तक ऊँची कर सकते हैं। जिसके कारण समुद्र तटीय शहर बम्बई, कलकत्ता, लक्षद्वीप आदि जलप्लावित होकर विलुप्त हो जायेंगे।

कार्बन डाईआक्साइड के अलावा एक खतरनाक गैस होती है क्लोरो–फ्लोरो कार्बन इस गैस का उपयोग ये कम्पनियाँ मुख्यतः रिहायशी चीजों के उत्पादन जैसे रेफ्रीजरेटर, फोटोकापियर, वातानुकूलित यन्त्र, एयरोसोल स्प्रे आदि में करती है।

आज प्रदूषण सम्बन्धी तकनीक के खिलाफ शिकायत की जा रही है, वह इन्हीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने गरीब देशों को बेची है। अब ये कम्पनियाँ दार्शनिक दलीलें देकर विकल्प–तकनीक को इन देशों को देने से इन्कार कर रही हैं। ताकि ये देश पर्यावरण के संकट को झेलते रहें। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि पर्यावरण के संकट भौगोलिक सीमाओं का आदर नहीं करते हैं। भस्मासुर की तरह वे भी इन संकटों की चपेट में आ जायेंगे।

संस्कृति पर हमला

क्या करूँ ? "इनकी साँस में बदबू है।" कहकर एक नयी नवेली पत्नी उदास हो जाती है। फिर उसकी एक सहेली उसे डाक्टर के पास ले जाती है। डाक्टर सलाह देता है कि "यदि साँस की बदबू से छुटकारा पाना है तो 'कॉलगेट का सुरक्षा चक्र' अपनाइये।"

इसी तरह से 'क्लोज अप फार क्लोजेज अस'। अर्थात् क्लोज–अप के इस्तेमाल से ही पति–पत्नी नजदीक आ सकते हैं। सवाल यह उठता है कि "क्या पति–पत्नि का रिश्ता एक चार–पाँच रूपल्ली वाली कोलगेट या क्लोज अप के पेस्ट की ट्यूब पर टिका हुआ है?" अगर आप "माल्टोवा माम" नहीं हैं तो पता नहीं आप अपने बच्चे को प्यार करती भी हैं या नहीं।

"आई एम ए काम्प्लान बॉय।"

"आई एम ए काम्प्लान गर्ल।" यानि लड़के या लड़की को पैदा करने के लिये माँ–बाप की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे या तो काम्प्लान के लड़के हैं या फिर कम्प्लान की लड़की।

इसी तरह बालों को काला बनाने तथा गिरने से बचाने के लिये कई तरह के हेयर डाई, तेल तथा दवाओं के विज्ञापन आते हैं। जबकि सच यह है कि अभी तक बालों को गिरने या सफेद होने से रोकने का कोई उपचार नहीं निकला है। लेकिन हर रोज ऐसे विज्ञापन टी.वी. पर आते रहते हैं जो लोगों के मन में सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं पैदा करते। यही बात दंत मंजन पर भी लागू होती है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी मंजन नहीं है जो दातों की बीमारियों को दूर कर सके या फिर दांतों को रोग लगने से बचाये। फिर भी टी.वी. पर या प–पत्रिकाओं में जिस तरह के चमकते हुये दांतों को दिखाया जाता है, वह किसी खास कम्पनी के मंजन के चमत्कार के रूप में होता है। एक के बाद एक सभी दांतों के खराब हो जाने पर भी लोग उपचार की दृष्टि से मंजनों की निरर्थकता को देख नहीं पाते।

किसी विशेष कम्पनी की साड़ी में सजी हुयी सुन्दर औरत, सूट में सजा हुआ सुन्दर नौजवान, कोका या पेप्सी की बोतल लिये समुद्र तट के रमणीक माहौल में खड़े सुन्दर स्त्री–पुरूष, विशेष कम्पनी के स्वीमिंग सूट में समुद्र तट पर क्रीड़ा करती हुयी बालायें – ये सब चटकीले–भड़कीले विज्ञापन ऐसा मानसिक माहौल तैयार करते है कि लोग विज्ञापन मॉडलों की सुन्दरता का राज विभिन्न परिधानों और कोका–पेप्सी में देखने लगते हैं। बड़ी तोंद वाले लालाजी और दो क्विंटल वजन वाली सेठानी भी इन कम्पनियों का सूट या बाथिंग सूट पहनकर अपने को हीरो–हीरोइन समझने लगते हैं। इस तरह सुन्दरता का अर्थ खास कम्पनी के परिधानों और सजावट में निहित होने लगता है। जबकि सुन्दरता किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और स्वभाव से आती है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सफलता उनके द्वारा की जाने वाली धुआंधार विज्ञापन बाजी में निहित है। प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये ये कम्पनियाँ विज्ञापनों पर खर्च करती है। वर्ष 1993–94 में कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विज्ञापन बाजी पर किये गये खर्च के आँकड़े नीचे दिये जा रहे है।

	बहुराष्ट्रीय कम्पनी का नाम	विज्ञापन पर खर्च
1	हिन्दुस्तान लीवर	90.00 करोड़ रूपये
2	आई.टी.सी	47.85 करोड़ रूपये
3	ब्रुक बाण्ड इण्डिया	47.57 करोड़ रूपय
4	कालगेट–पामोलिव	43.05 करोड़ रूपये
5	नेस्ले	32.35 करोड़ रूपये
6	गाडफ्रे फिलिप्स	32.45 करोड़ रूपये
7	गोदरेज–जनरल इलैक्ट्रिक	31.60 करोड़ रूपये
8	प्रॉक्टर एण्ड गैम्बिल	29.54 करोड़ रूपये
9	फिलिप्स	22.31 करोड़ रूपये
10	हरबर्ट सन्स	21.88 करोड़ रूपये
11	वी. एस. टी. इन्डस्ट्रीज	17.51 करोड़ रूपये
12	ग्लैक्सो	15.05 करोड़ रूपये
13	कैडबरी इण्डिया	14.53 करोड़ रूपये

14	ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज	14.23 करोड़ रूपये
15	रेकिट एण्ड कोलमैन	12.52 करोड़ रूपये
16	बी. पी. एल	14.47 करोड़ रूपये

इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विज्ञापनों ने एक खास किस्म की 'स्टेटस प्राब्लम' को जन्म दिया है। अब रोटी, कपड़ा और मकान वाली विचारधारा तो समाप्त हो चुकी है। उसकी जगह ले ली है नये–नये चिप्स, कुकीज, रैंगलर जीन्स, वॉल पेपर, आधुनिक टाइल्स आदि ने। भले ही श्रीमती जी दिन भर पड़ी सोती रहें, पर वैक्यूम क्लीनर न होने की वजह से उन्हें वक्त ही नहीं मिलता खाना बनाने का। या फूट प्रोसेसर जब नहीं होगा तो खाना बनाने में देर तो लगेगी ही, इसमें उनकी क्या गलती है। इनसबका परिणाम होता है अतार्किक एवं अनावश्यक व्यय, जो कि धीरे–धीर आपको तार्किक एवं आवश्यक लगने लगता है। 'स्टेटस सिंबल' पहले से ऊँचा होना रहता है लेकिन वेतन उस अनुपात में बढ़ता नहीं, नतीजा होता है व्यक्ति के अंदर एक द्वन्द्व प्रारम्भ होता है, जिसमें अधिकांशतः पलड़ा पिज्ञापनों का भारी रहता है। इस तरह एक ईमानदार व्यक्ति के भ्रश्टाचारी बनने की कहानी शुरू होती है यानि विज्ञापनों का रिश्ता भ्रष्टाचार से भी है।

विज्ञापनों मे कभी भी वस्तु को गुणवत्ता के आधार पर बेचने की कोशिश नहीं की जाती है। ये विज्ञापन तो मध्यम वर्ग के ग्लैमर को भुनाने की कोशिश करते हैं। ये विज्ञापन व्यक्ति में एक हीन भावना पैदा करते हैं। अधिकांशतः होता यह है कि विज्ञापित वस्तु होती मध्यमवर्ग के इस्तेमाल की है पर विज्ञापन में दिखाया जाता है, विशुद्ध रईसाना पांच सितारों वाली जीवन शैली। मध्यम वर्ग की एक कमजोरी होती है कि उसमें उच्च वर्गीय जीवन के प्रति एक विशेष किस्म की जिज्ञासा तथा वैसा जीवन जीने की दमित इच्छा होती है। विज्ञापन भयंकर सिद्ध होते हैं। एक आम आदमी चाहे जितनी भी विलासिता की वस्तुयें एकत्रित कर ले पर वह कभी भी उस किस्म की जीवन शैली को वहन नहीं कर सकता जैसी कि उसे विज्ञापन में दिखायी जाती है। इसका परिणाम होता है एक भीषण हीन भावना का जन्म, जो बढ़ती जाती है तथा एक सीमा के आगे जाने पर वैयक्तिक विघटन का करण बन जाती है।

विज्ञापन के इस स्वप्न संसार से जो विसंगतियाँ अल्प आय औश्र मध्यम आय वर्ग के पिरवारों में पनप रही हैं उनका सीधा परिणाम है कुंठा का जन्म। पाश्चात्य शैली के उपभोक्तावाद का यह हमला हमारे सारे नैतिक मूल्यों को नष्ट करता जा रहा है। विज्ञापन का यह जादुई संसार हमें रूमानी दुनिया में ले जाता है। बार–बार का दोहराव हमारे मन में उस वस्तु विशेष को पाने की लालसा पैदा कर देता है। फिर हमारा कोमल मन नैतिकता से परे धन संग्रह की ओर मुड़ जाता है। और प्रारम्भ हो जाती है एक अनवरत तृष्णा की दौड़ जिसका कही अंत नहीं है। इसी का फायदा अब ये कम्पनियाँ उठा रही हैं उपभोक्ताओं को ऋण मुहैया कराके। ये प्रलोभन देकर उपभोक्ताओं को अपनी ओर खींच रही है। इनका निशाना है सम्पन्न मध्यमवर्ग जिसकी संख्या लगभग 20 करोड़ है, यह अमरिका की कुल आबादी के बराबर बैइता है। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन शैली को जीने की लालसा पालने वाला यह वर्ग संवेदनहीन हो जाता है, जो किसी बदलाव के काम करने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। आधुनिक प्रचार माध्यमों और समाज के विशिष्ट सुविधाभोगी लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हमारे ऊपर विकृत उपभोक्तावादी 'फेंकू संस्कृति' लाद रही हैं। उनकी विज्ञापन बाजी से हमारा मानसिक दिवालियापन बढ़ रहा है। सारा का सारा उत्पादन मात्र 20 करोड़ लोगों के लिये हो रहा है।

अब तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने मनोरंजन परोसने के नाम पर अपने टेलीविजन नेटवर्क को शुरू कर दिया है। सी. एन.एन., स्टार, ए.टी.एन, एम.टी.वी., एल.टी.वी., यू.टी.वी. आदि अनेकों बहुराष्ट्रीय टेलीविजन कम्पनियों का जाल पूरे देश में फैल गया है। मनोरंजन के नाम पर बीसियों चैनल देश में चल रहे हैं। इन चैनलों पर दिखाये जाने वाले सीरियल, फिल्में तथा अन्य कार्यक्रम हमारे समाज को सांस्कृतिक रूप से खोखला बना रहे हैं। दो दर्जन से अधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इन विदेशी टी.वी. चैनलों के प्रमुख समय को खरीद लिया है। सीरियल तथा कार्यक्रमों में क्या संस्कृति दिखायी जायेगी, इसका फैसला बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पैसा तय करता है। यह इस देश में पहली बार हो रहा है जब सीरियल तथा अन्य कार्यक्रम कलाकर्मियों और रचनाकारों की कल्पना या भावना से नहीं बन रहे हैं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लुटेरों के निर्देशों पर बन रहे हैं। इस नये सांस्कृतिक उद्योग का सच यही है। आज हमारी संसकृति एक झटके में ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में चली गयी है। विदेशी चैनलों के कार्यक्रमों में एक समूची नई किस्म की उत्तेजक और भौंडी जीवन शैली दिखायी जा रही है। इसे देखकर दीनहीन, थके–हारे और निन्याबे बार असफल रहने वाले लोगों के मन में भी कामवासना जागृत हो जाती है। इन चैनलों परदिखाये जा रहे कार्यक्रमों या फिल्मों द्वारा एक घोषित सैक्स और हिंसा का युद्ध चलाया जात रहा है। इसका उद्देश्य व्यभिचार, यौनिक लिप्सा और हिंसा को बढ़ावा देना है। हिंसा और सैक्स की कुंठाओं के पनपने पर एक आम व्यक्ति ऐसी कल्पना का ताना–बाना बुन लेता है जो टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले दृश्य जैसी ही होती है। जब बार–बार यह कुंठित कल्पना दोहरायी जाती है तो फिर व्यक्ति के दिमाग में यह प्रयोग के रूप में दोहराने के अहसास को जीना चाहता है और यदि वह उसमें असफल रहता है तो फिर उसमें खालीपन

और हीनता पनपने लगती है। इसी खालीपन को भरने के लिये व्यक्ति को जब भी मौका लगता है तो वह चूकना नहीं चाहता। कुंठा और हीनता से भरा हुआ व्यक्ति अपना विवेक छोड़ देता है और फिर सैक्स और हिंसा के वही खेल खेलने लगता है जो टेलीविजन पर उसने देखा था। अब विकसित समाजों की भोगवादी संसकृति की विकृतियाँ हमारे यहाँ फैल रही हैं। इनसे मानसिक ओर आर्थिक गुलामी का पूरा ढाँचा हमारे ऊपर लद रहा है। आज हम अपनी जमीन से कट रहे हैं। सांस्कृतिक विलगन और आत्मनिर्वासन का संकट बढ़ रहा है। जिससे हमारी अस्मिता को ही गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आर्थिक दोहन से अधिक बड़ा खतरा है – मानसिक तौर पर परावलंबी होते जाना, इसी कारण हमारा आत्मविश्वास और अभिक्रम क्षीण हो रहा है।

राजनैतिक हस्तक्षेप

यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर लिया जाय तो उस देश की राजनीति अपने आप ही नियंत्रण में आ जाती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने दुनिया के तमाम देशों में इसी सिद्धान्त पर व्यापार किया है। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बढ़ती हुयी घुसपैठ ने राज्यों की सम्प्रभुता के लिये गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इन कम्पनियों के व्यापार करने के तरीकों के कारण अब राज्य की संकल्पना ही बेकार हो गयी है। 'राज्य की सम्प्रभुता', 'राज्य की नीति', 'राज्य की शक्ति', 'राजय की अखंडता' आदि शब्द अब अर्थहीन हो गये हैं। राज्य की नीतियाँ अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निर्देशों पर तय होती हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतान्त्रित देशों में से एक माने जाने वाले अमरीका की क्या हालत है ? यह अमरीकी सिनेटर सिलवेस्टर क्लार्क से 18 मार्च 1989 को 'न्यूर्याक टाइम्स' में प्रकाशित एक बयान से दिखती है "हमारे यहाँ विदेश्ज्ञ नीति सम्बन्धी निर्णय इन स्वयंभू प्रतिष्ठानों (बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) द्वक्षरा लिये जाते हैं, अब अमरीकी सरकार की अपनी पहल, भूमिका और उसके लचीलेपन में कमी आयी है।" इस कथन से यह बात साफ है कि अमरीकी सरकार के फैसलों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। यही अखबार (न्यूयार्क टाइम्स) आगे लिखता है कि "निजी बैंक, किसी सार्वजनिक बहस या निर्वाचित प्रतिनिधियों की देखरेख के बिना ही अमरीका की विदेशी आर्थिक नीतियों का निर्माण प्रभावी तरीके से कर रहे हैं।" एक उदाहरण से यह बात और स्पश्ट हो जाती है – फोटोकापी के उपकरणों का निर्माण करने वाली कम्पनी 'जेरॉक्स' की प्रबंध समिति इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि इसने कई बार अमरीका के 'फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन' के अधिकारियों से मिलने तक से इंकार कर दिया। ये अधिकारी कम्पनी से कुछ सूचनायें प्राप्त करना चाहते थे। 'जेरॉक्स' की प्रबंध समिति का मानना है कि अमरीका का 'संघीय व्यापार आयोग' बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की समस्याओं का समाधान करने के लिये उपयुक्त नहीं है।

अमरीकी सिनेटर मैरी गोल्डवाटर ने हाल ही में सीनेट में भाषण करते हुये कहा कि "आज हमारे लिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वही काम कर रही है, जो कुछ समय पूर्व तक सी.आई.ए. कर रहा था।" अमरीका के लिये तमाम तरह की गुप्त सूचनायें एकत्रित करने का काम अमरीकी कम्पनियाँ बहुत अच्दे से करती हैं। सी.आई.ए. के अतिरिक्त अमरीका की किसी भी संस्था या प्रतिष्ठान ने इतने संदेह और आलोचना को जन्म नहीं दिया जितना कि अमरीकी कम्पनियों ने। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बदनामी के मुख्य कारण हैं वे अपराध और गुप्त कार्यवाइयाँ जिनके पीछे इन कम्पनियों का हाथ रहता है। सच तो यह है कि आज ऐसे किसी भी बड़े राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विवाद को ढूँढ पाना कठिन है जिनके पीछे कहीं न कहीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्वार्थ नहीं जुड़े हों। आज ये कम्पनियाँ ही निर्धारित करती हैं कि तमाम देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों एवं अन्य नेताओं को किस प्रकार के सुर निकालने चाहिए ? ये कम्पनियाँ उन शासनाध्यक्षों/नेताओं के प्रति बहुत ही निर्मम होती हैं जो इन कम्पनियों की बात नहीं मानते। ऐसे लोगों को सीधे–सीधे उनके पदों से हआ दिया जाता है या उनकी हत्या तक करवा दी जाती है। उदाहरण के लिये – 1972 में चिली की जनता द्वारा चुनी गयी यूनिटी सरकार के विरूद्ध जो हिंसक षड्यंत्र रचा गया, वह पेप्सीकोला तथा आई.टी.टी. द्वारा संचालित

था। इस षड्यंत्र में चिली के राष्ट्रपति डा. सल्वादोर अलेंदे सहित 14 प्रमुख मंत्रियों की हत्या कर दी गयी। इस हत्याकांड में विख्यात कवि एवं साहित्यकार पाब्लो नेरूदा भी मारे गये। इस षड्यंत्र को इसलिये कराया गया क्योंकि डॉ. सल्वादोर अलेंदे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरोधी थे और अपने देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे। अपनी हत्या से कुछ घंटे पूर्व डॉ. आलेंदे ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में गुहार लगायी थी कि “मेरे देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शोषण से बचाया जाय।” संयुक्त राष्ट संघ के अधिवेशन में भाषण देकर जैसे ही डॉ. अलेंदे चिली लौटे उनकी सरकार का तख्ता पलट दिया गया और उनकी हत्या हो गयी। डॉ. अलेंदे के बाद जो सरकार चिली मे बनी, उसके लिये मुख्य चिन्ता बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को वापस बुलाने की थी, न कि देश के विकास का।

इसी तरह ब्राजील, बोलीविया और ग्वाटेमाला में सरकारों का तख्ता पलटने की साजिशों में अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रमुख हाथ रहा है। निकारागुआ की पिछले चार दशकों से चली आ रही त्रासदी के लिये भी अमरीकी कम्पनियाँ जिम्मेदार हैं। अल सल्वाडोर में नरसंहारों का जो सिलसिला एक बार इन अमरीकी कम्पनियों के इशारों पर शुरू हुआ था, वह आज भी बदस्तूर जारी है। ईरान में अहमद रजा शाह पहलवी के शासनकाल में अमरीकी कम्पनियों का प्रवेश हुआ और तभी से ईरान में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में यही हालात ईरान–ईरान युद्ध की परिणति बने। ईरान–ईराक युद्ध की समाप्ति पर सबसे अधिक सदमा 'लाकहीड' कम्पनी को पहुँचा, क्योंकि युद्ध के दौरान यह कम्पनी ईरान और ईराक दोनों को ही हथियार बेच रही थी। युद्ध की समाप्ति के बाद इस 'लाकहीड' कम्पनी ने ईरान में आंतरिक युद्ध पैदा कर दिया। इसी के चलते ईरान के मुजाहिदीनों को निःशुल्क हथियार दिये गये। ईरान की सरकार के खिलाफ मुजाहिदीनों को भड़काया गया। बाद में यही मुजाहिदीन भागकर अफगानिस्तान की सरहद पर एकत्रित होते रहे। हथियारों का जखीरा बढ़ता रहा। यही मुजाहिदीन अफगानिस्तान के लिये भी सिरदर्द बने। इन्हीं मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान की सरकार का तख्ता पलटा। फिर अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप हुआ। भयंकर खून–खराबा हुआ जो आज तक जारी है। हालांकि रूस ने अफगानिस्तान से अपनी फौजों का वापस बुला लिया है लेकिन अफगानिसतान में कत्लेआत जारी है। आज हालत यह है कि मुजाहिदीनों के घर में रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा लेकिन हथियारों का जखीरा भरपूर मिल जायेगा। अफगानिस्तान से सारे आर्थिक संसाधन युद्ध की ज्वाला में नष्ट हो चुके हैं। रोटी के एक–एक टुकड़े के लिये लोग पड़ोसी को मारने में नहीं चूकते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और एक अच्छा खासा देश बरबाद हो गया है। मुजाहिदीनों के कई संगठनों को अमरीकी कम्पनियों के हथियार मिल रहे हैं। ये हथियार ही इन संगठनों को बातचीत की मेज तक नहीं पहुँचने देते हैं। अमरीकी सरकार मुजाहिदीनों के कई संगठनों को सरकार बनाने का सपना दिखलाती है। इसलिये ये संगठन एक दूसरे के खिलाफ बन्दूकें ताने खड़े है और इससे अमरीकी कम्पनियों के हित सधे हुये है।

राजनीतिज्ञों से रिश्ते

26 फरवरी, 1976 को आर्थिक सहायोग और विकास संगठन की एक बैठक में ऐसी संहिता बनाने की मांग की गयी जा`रिश्वत व भ्रष्टाचार को गैर कानूनी करार दे सकें। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसका खुला विरोध किया। अमरीकी राष्ट्रपति का आग्रह था कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्ट्राचार विरोधी तमाम उपायों को स्वैच्छिक होना चाहिए ओर नैतिकअभिप्रेरणा पर आधारित होना चाहिए। इसके पीछे उनकी विशेष चिंता थी कि इस प्रकार के कानून बन जाने से अमरीकी कम्पनियाँ घाटे में पड़ सकती हैं, अतः इस नियम को बनने ही नहीं दिया जाय। इस बात के लिये अमरीकी राष्ट्रपति पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा दबाव डाला गया। तत्कालिन अमरीकी राष्ट्रपति ने 24 अन्य देशों का समर्थन जुटाकर भ्रष्ट्राचार विरोधी इस नियम को पारित नहीं होने दिया। मजे की बात यह है कि उसी दोरान अमरीकी कम्पनी 'लाकहीड' पर भ्रष्टाचार के लिये 2 साल 6 महीने तक मुकदमा चला। मुकदमें के फैसले स्वरूप लाकहीड को 6 लाख 47 हजार डालर का जुर्माना देना पड़ा। जबकि लाकहीड ने उस दौर का सबसे बड़ा 'भ्रष्टाचार कांड' करते हुये 224 लाख डालर की रकम रिश्वत के रूप में 19 देशों के शासनाध्यक्षों तथा अन्य लोगों को दी थी।

वे कौन से रिश्ते हैं जिनके चलते अमरीकी राष्ट्रपति तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की वकालत करते हैं और सिर्फ वकालत ही नहीं बल्कि इन कम्पनियों को बचाने का काम भी करते हैं। कम्पनियों को घाटा नहीं होने पाये यह अमरीकी राष्ट्रपति की चिंता में मुख्य रूप से शामिल रहता है। इन रिश्तों को समझने के लिये अमरीकी शासन तन्त्र में उच्च पदों पर बैठे हुये लोगों की खोज–खबर लेने की जरूरत है। सामान्यतः यह देखा गया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अधिकारियों की अमरीकी शासन तन्त्र में नियुक्ति होती रहती है। यह बात नीचे दिये गये कुछ उदाहरणों से स्पष्ट होती है – उदाहरण (1) पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन, राष्ट्रपति बनने के पहले रेडियों और टेलीविजन की कई कम्पनियों के मालिक थे। कुछ समय तक वे आई.टी.टी. के प्रमुख भी रहे। जॉनसन एण्ड जॉनसन नाम की बहुराष्ट्रीय कम्पनी के जनक भी लिन्डन बी. जॉनसन ही थे। (2) अमरीकी सरकारी खजाने के पूर्व सचिव विलियम ई. सिमोन, सचिव बनने से पहले कई अमरीकी बीमा कम्पनियों और बैकों के प्रमुख रह चुके थे। (3) अमरीका के पूर्व वाणिज्य सचिव फ्रेडरिक बी. डेन्ट, जी.ई.सी. के निदेशक रह चुके थे, अपने वाणिज्य सचिव बनने से पहले। (4) पेंटागन के पूर्व प्रमुख राबर्ट एस. मैकनमारा, पैंटागन में आने से पूर्व हथियार बनाने वाली कम्पनी आई.बी.एम. के अध्यक्ष थे। बाद में वे विश्व बैंक के भी अध्यक्ष रहे। (5) पूर्व अमरीकी विदेश सचिव जान बी. कोनेली, टेक्सास इन्स्टूमेन्ट्स कम्पनी के अध्यक्ष रहे। (6) अमरीका के एटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य करने वाले एन. कट्जेनखाव, बी. एफ.कार्पोरेशन के अध्यक्ष थे, एटॉर्नी जनरल बनने से पहले। (7) अमरीकी कानून विभाग के प्रमुख क्लार्क क्लिफोर्ड, यूनियन कार्बाइड के प्रबन्ध निदेशक रह चुके थे। (8) इंग्लैण्ड के प्रतिरक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख एडमिरल डी. एशमोर, हथियार बनाने वाली अंग्रेजी कम्पनी के अध्यक्ष रह चुके थे। (9) इंग्लैण्ड के गृह–नागरिक सेवा के प्रमुख डब्लू. आर्मस्ट्रांग, अंग्रेजी बैक 'मिडलैड' के अध्यक्ष रहे चुके थे। (10) इंग्लैण्ड के खजाना विभाग के प्रमुख ए. लोर्ड, डनलप कम्पनी के निदेशक रह चुके थे।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ और भ्रष्टाचार

अपने मुनाफों को अधिकतक बनाने के लिये ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ रिश्वत का सहारा लेती हैं और खूब भ्रष्टाचार करती हैं। ये कम्पनियाँ उन देशों के शासनाध्यक्षों और राजनेताओं को घूस देती हैं, जिन देशों में इन कम्पनियों का व्यापार होता है। घूस या रिश्वत देने की कारगुजारियों में वे सभी कम्पनियाँ शामिल पायी जाती हैं, जिनके नाम अकसर ही शानदार कारों, सैनिक साजो सामान या हवाई जहाजों पर दिखायी देते है दुनिया की प्रथम श्रेणी की सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, बड़े–बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने के लिये रिश्वत देती हैं। अक्सर जिन प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, पार्टी नेताओं या राष्ट्रपतियों के चित्र और नाम फैशनेबुल पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं, वे रिश्वत लेने के अपराधी पाये जाते है। रिश्वत लेने के सौदों में शामिल शासनाध्यक्षों ने कई बार रिश्वत देने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दिवालिया होने से बचाया है। उदाहरण के लिये; अमरीकी सरकार ने 'लाकहीड' कम्पनी को वित्तीय कठिनाईयों से उबरने के लिये अपनी गारंटी पर 25 करोड़ डालर के कर्जे निजी बैकों से दिलवायें 'लाकहीड' स्कैडल दुनिया के सबसे चर्चित स्कैंडलों में से एक रहा है। 'लाकहीड' तथा ऐसी ही कुछ अन्य कम्पनियों के रिश्वत देने के जो मामले सिद्ध हुये है, उनमें से कुछ को नीचे दिये जा रहा है –

- ☐ नीदरलैंड में रानी जूलियाना के पति राजकुमार बर्नहार्ड ने कई बार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से घुस ली। बर्नहार्ड फोकार एअरक्राफ्ट और रायल डच एयर कम्पनी (के.एल.एम.) के निदेशक थे। इसी कारण लाकहीड कम्पनी को उनमें दिलचस्पी थी। सन् 1961 से 1971 तक लाकहीड कम्पनी ने राजकुमार बर्नहार्ड को रिश्वत के रूप में 11 लाख डालर दिये।
- ☐ इटली के तत्कालीन राष्ट्रपति लिओने को भी 'लाकहीड' कम्पनी ने रिश्वत दी। इस कांड के खुलने के बाद राष्ट्रपति लिओने को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इटली के तत्कालीन गृहमंत्री ल्यूगी गुई को भी 'लाकहीड' स्कैंडल में फंसे होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। गृहमंत्री ने 'लाकहीड' कम्पनी के 14 सी – 130 परिवहन विमानों की खरीद को बढ़ावा दिया था। हालांकि इटली की जनता और विशेषज्ञ इसका विरोध कर रहे थे। विशेषज्ञों का कहना था कि इटली के स्वदेशी विमान, 'लाकहीड' के विमानों की तुलना में अच्छे और सस्ते हैं। लाकहीड के साथ हुयी समझौता वार्ता में इतालवी पक्ष ने लाकहीड को सूचित कर दिया था कि जब तक उनकी कृपा दृष्टि का बदला नहीं मिलेगा, सौदा नहीं हो सकता। 'लाकहीड' ने इस इशारे को समझ लिया और 22 लाख डालर से राष्ट्रपति, गृहमंत्री और रक्षामंत्री की जेबें गर्म कर दी।
- ☐ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तनाका, किशी और फुकुडा ने भी रिश्वत लेकर घोटाले किये। प्रधानमंत्री तनाका ने लाकहीड से रिश्वत खायी, जिसका आरोप सिद्ध हो जाने पर तनाका को जेल की सजा हुयी। प्रधानमंत्री किशी और फुकुडा ने अमरीकी कम्पनी ग्रुम्मन से 70 लाख डालर रिश्वत के रूप में लिये। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने भी 'लाकहीड' से 92 लाख डालर लिये।
- ☐ पश्चिमी जर्मनी के पूर्व रक्षामंत्री फ्रेंज जोसेफ स्ट्रस ने फाइटर विमानों के आर्डर देते समय 'लाकहीड' कम्पनी से 12 लाख डालर रिश्वत के रूप में स्वीकार किये। लाकहीड के इन विमानों

की अविश्वसनीयता के कारण इनका नाम 'उड़ते हुये कफन' रखा गया। पश्चिमी जर्मनी के राजनेता इस विमान को स्त्रियों को विधवा बनाने वाले विमान कहा करते थे।

☐ 80 के दशक में बोलिविया के राष्ट्रपति वेरियेंटोस ने गल्फ आयल कम्पनी से एक हेलीकॉप्टर प्राप्त किया था, जिसकी कीमत 1 लाख 10 हजार डालर थी। बोलिविया के राष्ट्रपति को इस कम्पनी ने अपनी शाखा खोलने के लिये 3 लाख 50 हजार डालर रिश्वत के रूप में दिये।

☐ ईरान में अहमद रजा शाह पहलवी ने अपने शासन के दौरान कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से रिश्वत खायी। बाद में जब इसका भण्डाफोड़ हुआ तब पता चला कि शाह के परिवार के सदस्यों ने भी रिश्वत खायी इस काण्ड में ईरान के कई उच्च नेता भी शामिल थे।

☐ हाल ही मे अमरीकी कम्पनी मैकडोनेल–डगलस ने, एफ–16 विमानों का आर्डर प्राप्त करने के लिये 15 लाख डालर, पाकिस्तान के राजनेताओं तथा अधिकारियों को दिये। इस बात पर कई बार पाकिस्तान की संसद में भी हंगामा हुआ है।

☐ मिस्र के इजरायल अधिकृत क्षेत्र में पश्चिम की कई बड़ी कम्पनी तेल की संभावना का पता लगाने में जुटी हुयी है। हाल ही में वहां एक रहस्यपूर्ण दुर्घटना घटी। पता चला कि समुद्र तट पर काम करने के लिये जरूरी उपकरण पास ही में स्थित ओमान में मौजूद है। अतः ओमान के अधिकारियों को 10 लाख डालर की रिश्वत, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये दी गयी कि जब ओमान का डेरिक (तेल की संभावना पता करने में काम आने वाला यन्त्र) चोरी किया जा रहा हो, तब वे इस पर ध्यान नहीं दें। इस प्रकार ओमान का वह डेरिक चुराया गया और इजरायल अधिकृत मिस्र के क्षेत्र में पहुंचा दिया गया।

☐ ईरान के शाह पहलवी से अमरीकी कम्पनी टाटे एण्ड लायले ने एक चीनी आयात के समझौते पर हस्ताक्षर करा लिये। बाद में पता चला कि ईरान को इस चीनी के आयात की कोई जरूरत नहीं थी; क्योंकि ईरान में पहले से ही उपलब्ध चीनी की मात्रा काफी थी। इस कारण ईरान को 4 करोड़ 50 लाख डालर का नुकसान हुआ और इस कम्पनी ने विश्व बाजार में चीनी की कीमतों से अधिक दाम वसूलकर अतिरिक्त मुनाफा कमाया।

☐ अमरीका के चर्चित 'वाटरगेट कांड' की जांच के समय यह पता लगा कि राष्ट्रपति निक्सन के निर्वाचन कोष में 17 अमरीकी कम्पनियों ने विशाल धनराशि दी। नोरथ्रोप कम्पनी ने 1,50,000 डालर, गल्फ आयल कम्पनी ने 1,00,000 डलर, फिलिप्स ने 1,00,000 डालर, ऐशलैंड ने 1,00,000 डालर, अमरीकी एयरलांइस ने 55,000 डालर और ब्रानिफ एयर कम्पनी ने 40,000 डालर दिये। चूंकि संघीय प्रत्याशियों के चुनाव अभियान में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा धन देना गैर कानूनी था, इसलिये वाटरगेट कांड निक्सन के लिये अत्यन्त ही दुःखदायी सिद्ध हुआ। इस कांड के खुलने पर निक्सन को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा।

☐ दक्षिण कोरिया में पार्क चुंग के शासनकाल में गल्फ आयल कम्पनी ने उर्वरकों व अन्य रसायनों का उत्पादन करने के लिये 35 करोड़ डालर की पूंजी लगायी। यह कम्पनी पार्क चुंग के कोष में 10 लाख डालर रिश्वत के रूप में दिये। थोड़े समय बाद जब पार्क चूंग के एक प्रतिनिधि ने, किसी राजनैतिक कार्य के लिये गल्फ आयल कम्पनी से 1 करोड़ डालर की मांग की तो कम्पनी ने इस मामले को प्रेस में लीक कर दिया। अखबारों में यह सारा मामला छपा

और दक्षिण कोरियामें काफी हंगामा हुआ। पार्क चुंग को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके शासन की छुट्टी हो गयी।

- हाल ही में बदनाम लाकहीड कम्पनी ने कोलंबिया में अपने विमान बेचने के लिये वहां के सेनानिवृत्त जनरल को 2 लाख डालर दलाली के रूप में दिये। स्पेन में इस कम्पनी ने अधिकारियों को 13 लाख डालर देकर, 2 करोड़ डालर के विमानों का आर्डर प्राप्त किया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति क्लार्क को इस लाकहीड कम्पनी ने 90 लाख डालर घूस के रूप में दिये। इस रिश्वत से लाकहीड कम्पनी को दक्षिण अफ्रीक में 10 करोड़ 17 लाख डालर के विमान बेचने का मौका मिला। लाकहीड ने सन् 1970 में इटली के रक्षामंत्री को 6 करोड़ डालर मूल्य के विमान बेचने के लिये 16 लाख डालर की रिश्वत दी।
- 1986 में हुआ बोफोर्स घोटाला तो अब जग जाहिर हो चुका है। 1986 में भारत सरकार ने स्वीडन की कम्पनी से 1700 करोड़ रूपये की 'एफ.एच.–77 बी. होवित्जर' तोपें खरीदी। इन तोपों की खरीद के बाद स्वीडन के रेडियों ने पर्दाफाश किया कि बोफोर्स कम्पनी ने इस सौदे में भारतीय अधिकारियों तथा कुछ राजनेताओं को लगभग 67 करोड़ रूपये की रिश्वत दी है। बोफोर्स कम्पनी ने भारतीय कानून की धज्जियां उड़ाते हुये सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुये लोगों को रिश्वत के दम पर अपने पक्ष मैं तैयार कर लिया। इस घोटाले की जांच संसदीय समिति द्वारा की गयी और आज तक जारी है। आलेफ पाल्मे इस बोफोर्स घोटाले के कुछ ऐसे रहस्यों को जानते थे, जिनके खुलने पर बोफोर्स कम्पनी को काफी नुकसान हो सकता था। अतः बोफोर्स कम्पनी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री को ही मौत की नींद में सुला दिया ताकि वे रहस्य उन्हीं के साथ दफन हो जायें।
- 1981 में भारत सरकार ने पश्चिमी जर्मनी की एक कम्पनी से 430 करोड़ रू. की पनडुब्बियाँ खरीदी थी। इस 430 करोड़ रू. के सौदे में लगभग 30 करोड़ रू. का घोटाला हुआ । जर्मनी की कम्पनी ने 30 करोड़ रू. दलाली के रूप में भारतीय अधिकारियों और नेताओं को दिये।
- 60 के दशक में चेकोस्लोवाकिया से भारत सरकार ने पिस्टल खरीदी थीं। इन पिस्टलों की खरीद फरोख्त में करोड़ों रू. की रिश्वत चेक कम्पनी ने भारतीय अधिकारियों को दी। संसद को इसकी जानकारी होने पर तत्कालीन रक्षामंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।
- अमरीकी कम्पनी नोरथ्रोप ने हाल ही में सऊदी अरब सरकार के साथ एफ–16 लड़ाकू विमानों का सौदा किया। इस सौदे में सऊदी अरब के शेख, वहां के वायुसेनाध्यक्ष तथा एक अन्य अधिकारी के 10 करोड़ 60 लाख डालर की रिश्वत दी गयी।
- अमरीकी कम्पनी नोरथ्रोप, इटली की कम्पनी टेलीफोन एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स, जर्मन कम्पनी सीमेन्स तथा जापानी कम्पनी निप्पन ने 1975 में ईरान में टेलीफोन का जाल बिछाने का ठेका प्राप्त करने के लिये, तत्कालीन ईरान सरकार को 20 लाख डालर रिश्वत के रूप में दिये।
- यूनाईटेड ब्राण्डस कम्पनी ने होण्डुरास देश में अपने विशाल फार्मों में पैदा होने वाले केलों पर निर्यात शुल्क में कमी कराने के लिये राष्ट्रपति ओसवॉल्डो लॉपेज को 10 लाख डालर रिश्वत रूप दिय। इस कांड का पर्दाफाश होने पर होण्डुरास के राष्ट्रपति ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली।

☐ जर्मनी की हैकलर एंड कॉख कम्पनी ने कोलंबिया की सरकर के साथ हुये एक सैनिक राइफलों की खरीद के सौदे में कोलंबिया के सैनिक अधिकारियों को 2 लाख डालर की रिश्वत दी।

☐ एशलैण्ड आयल कम्पनी ने हाल में ही गेबन देश के राष्ट्रपति अलबर्ट बर्नार्ड बोंगों तथा अन्य दो सरकारी अधिकारियों को 2 लाख डालर की रिश्वत देकर, गेबन में भूगर्भ तेल की खुदाई एवं सफाई का अधिकार पत्र प्राप्त किया। इस रकम का भुगतान कम्पनी ने अपने सामाजिक कल्याण कोष से किया।

☐ वर्ष 1993 में भरत में जो प्रतिभूमि घोटाला हुआ वह दुनिया के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़ा माना जाता है। इस घोटाले में देश्ज्ञ के लोगों के हजारों करोड़ रूपये डूब गये और फायदा हुआ विदेशी बैंकों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को। सरकार द्वारा जांच के लिये बनायी गयी संयुक्त संसदीय समिति ने स्पष्ट रूप से विदेशी बैंकों को इस घोटाले के लिये जिम्मेदार ठहराया। सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमरीका, ए.एन.जेड. गिन्डलेज और स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंकों नेपूरे घोटाले में अहम भूमिका निाायी इन बैंकों ने इस घोटाले के माध्यम से भारत के खून पसीने की कमाई का विदेशी मुद्रा भण्डार खाली कर दिया। क्योंकि इस घोटाले के माध्यम से हजारों करोड़ रू. की सम्पत्ति देश से बाहर चली गयी। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले में 60,000 करोड़ रूपये से भी अधिक की रकम शामिल है।

☐ 1994 में भारत में चीनी की कुछ कमी हो गयी। इस पर केन्द्र सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने चीनी के दाम बढ़ा दिय। अतः केन्द्र सरकार को बढ़े हुये दामों पर चीनी आयात करनी पड़ी। इससे देश को 360 करोड़ रूपये से भी अधिक का नुकसान हुआ। दूसरी और देश की आम जनता को अत्यन्त ही महंगी चीनी खरीदनी पड़ी। 12 रू. किलो वाली चीनी देश के गरीब लोगों को 18 से 20 रू. किलो में खरीदनी पड़ी

अफ्रीका में हस्तक्षेप

दक्षिण अफ्रीका राजनैतिक रूप से तो नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में लम्बे संघर्ष के बाद आजाद हो गया है लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अभी भी गुलाम है। रंगभेद और नस्लवाद की समस्या आज भी दक्षिण अफ्रीकी समाज में बनी हुयी है। नस्लवाद की इस समस्या की जड़े वहां के समाज में अत्यन्त ही गहरी हैं। नस्लवाद के जहर को दक्षिणी अफ्रीकी समाज में फैलाने का काम अमरीका, ब्रिटेन तथा कुछ अन्य यूरोपीय देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने बहुत ही बेहयाई के साथ किया है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ दक्षिणी अफ्रीकी नस्लवादी सरकार का शुरू से ही समर्थन करती रही है। डब्लू.पी. बोथा और एफ.डी. क्लार्क के शासनकाल में इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने वहां की जनता के राष्ट्रवादी आन्दोलन को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन कम्पनियों ने बोथा और क्लार्क सरकार को जोरदार समर्थन किया, जबकि पूरी दुनिया में इन सरकारों के खिलाफ प्रतिबन्ध लगे रहे।

यह सारा खेल अमरीका, इंग्लैण्ड, पश्चिमी जर्मनी व फ्रांस के निगमों के इशारे पर हुआ। दक्षिण अफ्रकी गणराज्य में 1600 से अधिक निगम कार्य कर रहे हैं जिनके वहां पर मोटे तौर पर 1700 करोड़ डालर के प्रत्यक्ष निवेश व 2300 करोड़ डालर के पत्राधान निवेश हैं। इनमें

600 से अधिक इंग्लैण्ड के, 400 से अधिक अमरीका के, 130 से अधिक प. जर्मनी के निगम मोजूद है जिनकी आर्थिक धमनियों में दक्षिण अफ्रीकी नस्लवादी शासन का सुनहरा जीवन रक्त बहता रहा है। दक्षिण अफ्रीकी अर्थतन्त्र में अमरीका के प्रत्यक्ष निवेश 2000 करोड़ डालर के है। दक्षिण अफ्रीका के समस्त उद्योगों का 72 प्रतिशत हिस्सा विदेशी पूंजी के नियंत्रण में हैं। बहुराष्ट्रीय निगमें दक्षिण अफ्रीकी प्राकृतिक संसाधनों का जबर्दस्त शोषण करके भारी मुनाफा बटोर रहे है। दक्षिण अफ्रीका का 'फिनांशियल मेल' बताता है कि इंग्लैण्ड की कम्पनियाँ 31 प्रतिशत मुनाफे कमा रही है। अमरीका की कम्पनियां 27 प्रतिशत मुनाफे कमा रही है। जो दुनिया के अन्य हिस्सों में उसके मुनाफों की तुलना में कहीं ज्यादा है। निवेशकों की नजर में दक्षिण अफ्रीका हमेशा ही सोने की खान रहा है। एक ऐसी स्फूर्तिदायक जगह वहां मुनाफे तगड़े है और समस्यायें कम।

खान उद्योग में काम करने वाले 90 प्रतिशत काले लोग है ओर उनकी आमदनी सफेद लोगों की तुलना में मात्र 5 प्रतिशत है। निर्माण उद्योग में काम करने वालों में आधे अफ्रीकी है। वहाँ उनकी आय गोरे लोगों की तुलना में 17 प्रतिशत है। एक सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैण्ड, अमरीका, स्वीडन व प. जर्मनी की निगमें जो पैसा अफ्रीकियों को अदा करते है वह गरीबी की रेखा से भी बहुत नीचे है अर्थात् उसे पैसे से आवश्यकता भर भोजन, कपड़े भी नहीं खरीदे जा सकते है। चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिये।

पश्चिमी देशों की सरकारें नस्लवाद और पृथकता की भर्त्सना तो बड़े जोरदार शब्दों में करती हैं पर जब कुछ ठोस काम करने की बात सामने आती है तो वे बिल्कुल विपरित ढंग से पेश आती हैं। वे दक्षिण अफ्रीका में यथास्थिति को बनाये रखने में अपनी मौजूदा विशाल आमदनी की गांरटी और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के विरूद्ध संघर्ष करने का एक आधार देखती रही है। इस प्रकार ये सारी जनता की स्पष्ट उपेक्षा ही नहीं करते बल्कि वे वास्तव में हर प्रकार का अपराध करने के लिये भी तैयार है।

जब दुनिया भर में दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी अत्याचारों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शित किया जाता रहा और विभिन्न देशों में रंगभेदवाद की हुकूमत के विरूद्ध अनेक जन–अभियान छेड़े गये, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी निन्दा करते हुये अनेक प्रस्ताव पारित किये और सुरक्षा परिषद ने इसके विरूद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने के निर्णय लिये, लेकिन इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर कोइ असर नहीं हुआ। निक्सन के समय में अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने नीति संबंधी एक गुप्त दस्तावेज एन.एस.एम.–39 स्वीकृत किया था जिसमें दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकारों के साथ समझ–बूझ कर संपर्क और संचार का विस्तार करने का आव्हान किया था। दक्षिण अफ्रीका के प्रति पश्चिमी देशों की नीति दो प्रकार की रही – एक सरकारी जिसमें नस्लवाद और पृथकतावाद के विरूद्ध शाब्दिक धमकी आती थी, और दूसरी कार्यवाही संबंधी जिसमें जन–आक्रोश के विरूद्ध नस्लवादियों का बचाव करने की कार्यवाईयाँ शामिल थीं। आज ये निगमें अंगोला, मोजाम्बीक, अफगानिस्तान ओर हाल में ईरान के उदाहरणों से भयभीत हैं। सरकारों का मुख्य काम विदेश नीति को उस वास्तविकता के अनुकूल बनाना है जिसे इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने काफी पहले पैदा किया था। ये कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में पूँजी लगाने का वातावरण बहुत अनुकूल है और इस कारण इसे नयी विश्व अर्थव्यवस्था में एक उपयोगी भूमिका अदा करनी है बेशक उसकी भूमिका होगी पर केवल इन बहुराष्ट्रीय निगमों के लिये।

निगमों के साथ संबंधों का मजबूत करने के लिये जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है यह सरकार उसमें कोताही नहीं बरतती है। उदाहरण के लिये, इसने सिडनी एस. बैरन एंड कम्पनी को प्रतिवर्ष 3,65,000 डालर के स्थान पर 6,50,000 डालर देना शुरू कर दिया है, यह कंपनी अमरीका में दक्षिण अफ्रीका में हितों को पूरा करने के लिये काम करती है। अमरीकी व्यवसायियों के साथ संपर्कों का बढ़ाती है; आकर्षक सौदों के समझौते करने में मदद करती है जिसमें हथियारों से संबंधित सौदे भी शामिल हैं। जो अन्तर्राष्ट्रीय निगम अफ्रीकी लोगों की हत्या करके पैसा बना रहे हैं उनके ट्रेडमार्क उस हर गोली पर दिखायी दे सकते हैं जो अश्वेत प्रदर्शनकारियों पर छोड़ी जाती है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार को भेजे जाने वाले हथियार अत्यन्त चक्करदार रास्तों से पानी जहाज द्वारा लाये जाते हैं जो सी.आई.ए, प. जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर सेवाओं द्वारा निर्धारित किये जाते है। उदाहरण के लिये अमरीका निर्मित लड़ाकू विमानों को ले लीजिये, उनके हिस्सों को इटली में जोड़ा जाता है, फिर इजरायल को बेचा जाता है और दक्षिण अफ्रीका तक उन्हें प. जर्मनी के जहाजों द्वारा सिंगापुर होकर पहुँचाया जाता है। यही लड़ाकू विमान रोडेशिया में मुक्ति आंदोलन को कुचलने के लिये वहाँ की सरकार को सौंपे गये थे।

दक्षिण अफ्रीका गणराज्य उन थोड़े से देशों में से एक है जिसने नाभिकीय हथियारों के बढ़ाव को रोकने की संधि पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है, हालांकि 100 से अधिक देशों ने इसे स्वीकार किया है। इसी वजह से उन पश्चिमी ताकतों की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती हैं कि जो हथियारों के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका को मदद न देने के संयुक्त राष्ट्र संघ के सुविदित निर्णयों का उल्लंघन करके स्वयं अपनी नाभिकीय क्षमता का विकास करने में नस्लवादियों की सहायता कर रहे हैं। इजरायल इसमें विशेष रूप से सक्रिय है। नाभिकीय हथियारों के बढ़ाव को रोकने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर न करने वालों में वह भी एक है। पश्चिमी बहुराष्ट्रीय निगमों को दक्षिण अफ्रीका में नभिकीय उत्पादन करते हुये अब 25 वर्ष से अधिक हो चुके हैं।उन्होंने नस्लवादियों को नाभिकीय ईधन व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी है। जोहांसबर्ग में यूरेनियम को समृद्ध बनाने का एक विशाल समुच्चय खड़ा किया जा चुका है। प्लूटोनियम के रेडियों सक्रिय आइसोटोपों के उत्पादन का काम जारी है। इन सभी कार्यो में मुख्य भूमिका प. जर्मनी की सीमेन्स, लुर्गी और लेकोल्ड तथा ए.जी., अमरीका की फोक्सबोरो और फेडरल प्रोडक्ट्स कंपनियाँ अदा कर रही हे। यह बात काबिले गौर है कि यूरेनियम को समृद्ध बनाने के जो उपकरण भेजे जा रहे हैं उसमें नाटो की भागीदारी है। इंग्लैण्ड की रियो–टिटो–जिंक, फ्रांस की टोटल मिनेरेएट न्यूक्लियारे, ई.एल.एफ. एक्यूटेआइन नामक कंपनियों ने नाभिकीय कच्चे माल की दौड़ में अपने प्रयासों को एकजुट कर लिया है। उन्होंने 5,000 टन यूरेनियम आक्साइड निकालने के लिये नामीबिया में एक विशाल खान 'शौसिंग' का निर्माण कर लिया है। इस आशय के समाचार मिले हैं कि दक्षिण अफ्रीका इजरायल को यूरनियम की आपूर्ति करेगा और इजरायल दक्षिणी अफ्रीका को नाभिकीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायेगा। गत वर्ष सितंबर में दक्षिण अफ्रीकी तटों पर जिस रहस्यपूर्ण कौंध को देखा गया था वह इजरायल द्वारा किया गया नाभिकीय विस्फोट था, जिसे दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से किया गया था।

मई 1985 मे बहुराष्ट्रीय निगमों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग के अधिवेशन में अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने यह मांग करते हुये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि इन नस्लवाद को

समर्थन देने वाली निगमों के विरूद्ध कड़े कदम उठाये जायें और उन सारे निवेशों को वापस कर लिया जाय जो नस्लवादियों की सहायता कर रहे हैं। प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये नाईजीरिया के राजदूत एल.ओ. हेरीमेन ने घोषणा की थी कि "निगमों ने नस्लवादी सरकारों के अत्याचारों की सहायता इसलिये की है कि वे भ्झी अपने अपार मुनाफों को बनाये रखने के यिे वहां यथास्थिति कायम रखना चाहती हैं। ये कम्पनियाँ अफ्रीकी लोगों में आत्म सम्मान के विरूद्ध होने वाली हिंसा में तथा उस अत्याचार में नस्लवादी सरकारों की भागीदारी एवं सहयोगी हैं। जिनके कारण जनता को अपार मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं।" समाजवादी देशों, एशिया व लैटिन अमरीका के देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और यह स्वीकार कर लिया, लेकिन इंग्लैण्ड, अमरीका, फ्रांस व जर्मनी ने इसका विरोध किया। पहले भी 1997 में, 198 में तथा 1979 में अनेक ठोस प्रस्ताव रखे गये थे और उनमें प्रिटोरिया के साथ बहुराष्ट्रीय निगमों के सैनिक सहयोग को उजागर करने की आवश्यकता पर ध्यान खींचा गया था।

दक्षिण अफ्रीका में स्थापित कुछ महत्वपूर्ण निगमों के अध्यक्षों की टिप्पणी जो कि लंदन के दैनिक 'मोर्निंग स्टार' में छपी है –

जनरल मोटर्स : "हमें वहाँ 50 वर्ष से ऊपर हो गये है और हमारी योजना वहाँ लंबे समय तक रहने की है............."

कालटेक्स पेट्रोलियम : 3हम नया पूंजी निवेश इसलिये कर रहे हैं कि बाजार फैलता जा रहा है................"

मेनहेट्टन बैंक : "हम पहले की भाँति काम कर रहे है शीघ्र ही हम और बड़े क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे........"

गुडईयर : "हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है जिसके कारण हमें यहाँ से बाहर जाना पड़े.........."

एक अमरीकी प्रवक्ता : "अधिकांश अमरीकी कम्पनियाँ पहले की तरह चल रही हैं.............."

इन निगमों को विश्वव्यापी भर्त्सना के सम्मुख निश्चय ही बचाव करना पड़ता है। नस्लगत असमानता को समाप्त करने के लिये इन कें पाखंडपूर्ण चरित्र का जब 'मोर्निंग स्टार' द्वारा भंडाफोड़ किया गया तो सामने आया कि :–

"अफ्रीकी यूनियन के नेताओं ने मांग की कि जनरल मोटर्स के पोर्ट एलिजाबेथ स्थित कारखाने के पेशाबघरों के दरवाजे से रंगभेद सूचक बोर्ड हटा लिये जाये। जनरल मोटर्स ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे हटा लेंगे। लेकिन अब पजा चला है कि उन्होंने वे बोर्ड तो हटा लिये हैं पर उनके स्थान पर रंगीन चाभियों वाले दरवाजे लगा दिये है: "गोरों के लिये नीले तथा कालों के लिये नारंगी"।

यह रवैया प्रत्येक क्षेत्र मेंपाया जात है। प्रिटोरिया सरकार अधिक से अधिक बोर्ड बदलने का कार्य करती है लेकिन भेदभाव कायम है। अमरीकी पत्रिका 'साइंस मोनीटर' में छपे एक इंटरव्यू में वहाँ की कार फर्मे इस बात पर एकमत हो गयी हैं कि वे उन संगठनों को चुदा नहीं देंगी जो काले लोगों के हितों की देखभाल करते हैं।

इंग्लैण्ड, अमरीका व अन्य देशों की कंपनियाँ अब बड़े स्तर की व्यापारिक कार्यवाईयों पर अधिक भरोसा नहीं करती हैं, वह नस्लवादी नीति में अब मध्यमवर्गीय व्यवसायियों और छोटी

मछली फंसाने पर आमादा है। उनकी सलाह यह है कि अच्छी आय को सुनिश्चित करने के लिये उन कम्पनियां के शेयर खरीदने चाहिऐ जो दक्षिण अफ्रीका में काम कर रही हैं। सीधा सा तर्क यह है कि निगमों की अमानवीय नीतियों में यथासम्भव अधिक से अधिक लोगों को फंसाया जाय और इस प्रकार केवल 5 या 10 डालर फेंक कर की उनको इच्छा या अनिच्छा पूर्वक नस्लवादी अपराध में भागीदार बना लिया जाय।

दक्षिण अफ्रीका की अनेक कंपनियाँ जिनमें अनेक तो पश्चिमी निगमों की सहयोगी कंपनियाँ हैं, लैटिन अमरीका में विशेष दिलचस्पी दिखा रही है। दक्षिण अफ्रीका चिली के साथ मिलकर व्यापार करता है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित आंग्ल अमरीकी कम्पनी ने, जो दक्षिण अफ्रीका स्थित दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली कम्पनी है, ब्राजील में सोने के खनन की विशाल फर्म में 65 प्रतिशत शेयर खरीद लिये है। पीकिंग भी अब प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ हाथ मिला रहा है। चिली की तानाशाही सरकार को पीकिंग से सहायता मिल रही है।

बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायता से लैटिन अमरीकी 'गुरिल्ले' और दक्षिण अफ्रीकी नस्लवादी, दक्षिण अटलांटिक में एक सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक संघ का पवित्र गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्रांतिकारी और मुक्ति आंदोलनों को रोका जा सके। इस प्रकार के विचारों को नाटो के सेनाध्यक्षों ने और निगमों के आकाओं ने एक लंबे समय से पाला पोसा है और समर्थन दिया है। दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य और अर्जेटीना की सरकार ने युद्ध सामग्री बनाने वाले निगमों के बची सूचनाओं और विशेषज्ञता का आदान–प्रदान करने की व्यवस्था भी है। अर्जेटीना द्वारा प. जर्मनी के निगमों से नाभिकीय प्रौद्योगिकी खरीदे जाने को देखते हुये यह आदान–प्रदान विशेष महत्व का हो जाता है। पर यह बात निश्चित है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विदेशों में कितनी ही पूँजी क्यों न लगायें, यह नस्लवाद और पृथकतावाद बचने वाला नहीं है, उसका अन्त तो निश्चितृ है, उदाहरण जिम्बाब्वे में देश भक्तों की विजय में लक्षित है।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और भारत

जो धन देता है, वह अपनी धुन भी बजवाता है। ये विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ दुनिया के जिस देश में काम कर रही हैं, वहाँ अपनी धुने बजवा रही है। हमारा देश भी कोई अपवाद नहीं है।

जून, 1990 में भारत सरकार ने नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। यह नीति पूरी तरह से विश्व बैंक के प्रभाव में बनी है जो कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पुरोहिताई करता है।

विश्व बैंक ने 'भारत के व्यापार सुधार के लिये नीति' विषयक रिपोर्ट सं. 8995–आई. एन. 30 नवम्बर 1990 को तैयार कर भारत सरकार को सौंपी थी। 21 जून 1991 को शपथ ग्रहण करने के बाद ही नरसिंह राव सरकार ने विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में दिये गये निर्देशों को लागू करना शुरू कर दिया। प्रस्तुत तालिका में विश्व बैंक की शर्तों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की गयी की मुख्य बातों का उल्लेख किया जा रहा है :–

आर्थिक नीति के पुर्नगठन के लिये विश्व बैंक की शर्ते	**विश्व बैंक रिपोर्ट का पैरा सन्दर्भ**	**1991–92, 92–93, 93–94 के बजट में केन्द्र सरकार द्वारा मानी गयी शर्ते**
1. राजकोषीय घाटे में कमी करने के साथ–साथ मुद्रा दर को संशाधित किया जाये मुद्रा विनिमय दर का कम से कम 21 प्रतिशत अवमूल्यन किया जाये।	2.19, 4. 50, 8.62, 9.13, 9. 51, 9.45	☐ 1990–91 राजकोषीय सकल घरेलू उत्पाद का 8.4 प्रतिशत था। 1991–92 में इसे 6.2 प्रतिशत तथा 1992–93 में 5 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया। 1993–94 में इसे 4.7 प्रतिशत पर ला दिया गया है। ☐ 1 जुलाई 1991 को डालर के मुकाबले रूपये का 9.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। 3 जुलाई 1991 को पुनः रूपये का 12.82 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया गया। 92–93 में रूपये को 60:40 के अनुपात में आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया। जिसके चलते 60 प्रतिशत परिवर्तनीय हिस्से का 19.8 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया। 93–94 के बजट में रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का फैसला कर सरकार ने विश्व बैंक के निर्देशों का तकरीबन पूरे तौर पर पालन कर दिया।
2. व्यापार नीति में संशोधन के निर्देश (क) भारतीय उद्योगों को आयात के प्रति संरक्षण समाप्त	9.16	☐ 6 अक्टूबर 1991 को राज्य व्यापार निगम एवं धातु व्यापार निगम का चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में एकाधिकार समाप्त कर इन्हें निजी ट्रेडिंग हाऊस के समकक्ष बनाया गया। कुछ

कर, आयात नियंत्रण समाप्त किए जाये।		आवश्यक बनाया गया। कुछ आवश्यक वस्तुओं (पेट्रालियम, खाद्यान्न, खाद्य तेल, उर्वरक आदि) को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं विसरणीकृत
(ख) आयात की नकारात्मक सूची एक बनाये जाये एवं संक्षिप्त किया जाये।	4.50, 4. 55, 9.24	☐ नयी आयात–निर्यात नीति में केवल 8 वस्तुएं सारणीबद्ध 17 सितम्बर 92 को डी.ए.पी. उर्वरक और 21 सितम्बर को विमाटिन ए व उसका पैरामिक्स विसरणीकृत किया गया।
(ग) पूंजीगत वस्तुओं एवं मध्यवर्तियों के आयात पर लाइसेंस समाप्त किया जाये।	9.45	☐ शीर्ष टैरिफ स्तर 300 प्रतिशत से कम कर 150 प्रतिशत किया गया। 91–92 में सीमा शुल्क में 744.5 करोड़ रूपये की छूट दी गयी। 16 जनवरी 92 को इस्पात की वस्तुओं पर आयात शुल्क घटा दिया गया।
(घ) सरणीबद्ध वस्तुओं का आयात करने वाली सरकारी एजेन्सियों का एकाधिकार समाप्त किया जाये तथा इन्हें लघु क्षेत्र के लिये आयात की भूमिका निमाने हेतु कहा जाये।	9.20	☐ 31 दिसम्बर 92 को नेथ्था विसरणीकृत किया गया। शुल्क खंड़ों की संख्या, चार कर शीर्ष टैरिफ स्तर 110 प्रतिशत किया गया। सीमा शुल्क में 2035 करोड़ रूपये की छूट दी गयी।
(ड) सीमा शुल्क कम कर न्यूनतम स्तर या शून्य स्तर पर लाया जाये अन्यथा समान सीमा शुल्क दर 20 प्रतिशत की जाये। शुल्क के खंडों की संख्या तीन की जाये।	5.36, 6. 47, 9.19, 9. 29, 9.27, 9.32	☐ 93–94 के बजट में शीर्ष टैरिफ स्तर 85 प्रतिशत किया गया। सीमा शुल्क में 3273 करोड़ रूपये की छूट दी गयी। ☐ 92–93 में कोयला खनन, पेट्रोलियम शोधन, ऊर्जा परियोजना के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 30 प्रतिशत किया गया।
(च) पूंजीगत सामान व मध्यवर्तियों पर औसत 30 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगाने का निर्देश	9.45	☐ 92–93 में परियोजना आयातों और सामान्य मशीनरी पर सीमा शुल्क 85 प्रतिशत से घटाकर 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रानिक पर 50 प्रतिशत कर दिया गया। अन्य पूंजीगत सामानों पर सीमा शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत तक कर दिया गया। मध्यवर्तियों पर रियायती सीमा शुल्क का प्रावधान रखा गया।
(छ) उपभोक्ता वस्तुओं को आयात की नकारात्मक की नकारात्मक सूची से निकालकर आयात की अनुमति दी जाये तथा सीमा शुल्क कम किया जाय। सीमा शुल्क कम न करने की स्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं	9.23, 9. 24, 9.32	☐ 1993–94 बजट में कोयला खनन, पेट्रोलियम पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत, विद्युत परियोजनाओं पर 20 तथा परियोजना और सामान्य मशीनरी पर 35 प्रतिशत रखने का फैसला लिया गया। ☐ 9 फरवरी 1992 को यात्री सामान के साथ 35 घरेलू इलैक्ट्रोनिक उपकरण लाने की अनुमति दी गयी। 1 यात्री 1.50 लाख रूपये मूल्य के

पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया जाये।		उपभोक्ता उपकरण 150 प्रतिशत शुल्क देकर ला सकता है। इससे पूर्व सीमा शुल्क 225 प्रतिशत था। ☐ 93–94 के बजट में यात्री सामान के साथ 1.50 लाख रूपये मूल्य की सभी वस्तुएं लाने की छूट दे दी गयी।
3. निर्यात नीति में संशोधन के निर्देश (क) निर्यात, व्यवस्था में प्रशासनिक सुधार किए जायें तथा निर्यात नीति को सरल बनाया जाये। (ख) रैप लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाया जाये तथा इसे संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में अपनाया जाये। (ग) राजकोष पर भार पड़े बिना निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाये। (घ) निर्यातोन्मुखी उद्योगों को मशीन आयात पर शुल्क में छूट दी जाये। यह छूट तीन से पांच वर्ष में दी जा सकती है	6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 4.54, 6.50 4.56 6.49, 9.38 9.34, 9.35	☐ 91–92 में निर्यात लाइसेंसो की जटिल प्रक्रिया समाप्त कर सरल व्यवस्था अपनायी गयी। ☐ निर्यातित वस्तुओं की विभिन्न सूचियाँ समाप्त कर एक नकारात्मक सूची बनायी गयी। ☐ 91–92 में रैप लाइसेंस की एक्जिम स्क्रिप में बदला गया। ☐ सभी प्रकार के निर्यात पर 30 प्रतिशत एक्जिम स्क्रिप देने की घोषणा की गयी। ☐ 4 जुलाई 91 को निर्यात के लिए, नकद मुआवजा सहायतासमाप्त कर, सभी आयात (पेट्रोलियम, खाद्य तेल, खाद्यान्न एवं उर्वरक को छोड़कर) एक्जिम स्क्रिप से करने की अनुमति दी गयी। ☐ 92–93 में रूपये को आंशिक परिवर्तनीय बनाने के बाद एक्जिम स्क्रिप समाप्त कर दिया गया। ☐ निर्यात संवर्धक पूंजीगत सामान के आयात में सीमा शुल्क में छूट दी गयी।
4. सीमा शुल्क कम करने से होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए उत्पादन शुल्क, आयकर एवं घरेलू कर में वृद्धि की जाये।		☐ 91–92 में विशेष उत्पादन शुल्क दो गुना किया गया। उत्पादन शुल्क में कुल 1799 करोड़ रूपये और आयकर में 2139 करोड़ रूपये की वृद्धि की गयी। ☐ 92–93 में उत्पाद शुल्क में कुल 2515 करोड़ रूपये तथा प्रत्यक्ष करों में 795 करोड़ रूपये की वृद्धि की गयी। चेलैया समिति ने अति लघु और कुटीर उद्योगों पर भी उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव दिया है।
5. जो वस्तुएं उत्पाद शुल्क के दायरे में नहीं हैं, उन पर	5.31, 5.34,	☐ चेलैया समिति ने उर्वरकों पर 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव देते हुए, कई

उत्पादन शुल्क लगाया जाये। (विश्व बैंक ने उर्वरक, कीटनाशक, कृषि और औषधियों पर उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव दिया था।)	9.34, 5.32, 5.41 5.36, 5.39, 9.34	वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव दिया है।
6. उत्पादन कर प्रणाली में परिवर्तन कर मोडवेटस वेट प्रणाली अपनायी जाये।		☐ चेलैया समिति ने मोडवेट व वेट प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया है।
7. औद्योगिक नीति में परिवर्तन कर उद्योगों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया जाये।	1.1, 9.64	☐ जुलाई 91 में घोषित नयी औद्योगिक नीति में लाइसेंसे प्रणाली परिवर्तित कर सिर्फ 18 उद्योगों के लिए ही लाइसेंसे की जरूरत रखी गयी। उद्योगों में अब विदेशी कम्पनियाँ शत–प्रतिशत निवेश भी कर सकती है। ☐ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित 17 उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गयी। ☐ 5 मार्च 93 को घोषित नयी राष्ट्रीय खनिज नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कई उद्योगों को निजी क्षेत्र में देने का फैसला किया जाय।
8. उद्योगों को प्राप्त संरक्षण समाप्त किया जाये। आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा खरीद में घरेलू उद्योगों को दी जा रही प्राथमिकता बंद की जाये।	अध्याय – 7, 4.25	☐ 16 जनवरी 92 को इस्पात नियंत्रण मुक्त किया गया और खरीद में घरेलू उद्योगों को दी जा रही प्राथमिकता भी समाप्त कर दी गयी। ☐ 92–93 में फोस्फेटिक उर्वरक और केरोसीन व रसोई गैस वितरण को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया।

9. सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन करते हुए घाटे में चलने वाली इकाइयों को बंद किया जाये।	8.67, 9. 13, 9.63	☐ नयी औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्गठन की घोषणा की गयी और रूग्ण उद्योगों को औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष भेजने का फैसला लिया गया।
10. उद्योगों में अतिरिक्त कर्मचारियों की छटनी की जाये, इसके लिए बहिर्गमन नीति अपनायी जाये और उससे प्रभावित कर्मचारियों के संरक्षण हेतु कोष निर्मित किया जाये।	8.66, 9. 64, 9.67	☐ 91–92 में स्वर्णिम विदाई योजना एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने का फैसला लिया गया। ☐ 91–92 में बहिर्गमन नीति से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए पुनर्निर्माण कोष बनाने की घोषणा करते हुए 200 करोड़ रूपये काकोष बनाने का निर्णय लिया गया। ☐ 92–93 में इस कोष के लिए 1000 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गयी।
11. सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचे जाये।	9.62	☐ 91–92 में 31 उपक्रमों के 3038 करोड़ रूपये के शेयर बेचे गये। ☐ 92–93 में 3500 करोड़ रूपये के शेयर बेचने का लक्ष्य रखा गया था, इनमें से 13 उपक्रमों के 1866 करोड़ रूपये के शेयर बेचे गये। इस प्रकार दो वर्षों में कुल 4904 करोड़ रूपये के शेयर बेच दिये गये।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का असली चेहरा

मरे हुये लोगों को जलाकर कमाई करने वली दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'इन्टरनेशनल सर्विस कार्पोरेशन' (I.S.C.) है। इसके पास विश्व भर में 502 शवदाह गृह हैं। यह कम्पनी शवों को जलाकर एक वर्ष में औसतन 69 करोड़ 28 लाख 17 हजार डालर (13 अरब 16 करोड़ 35 लाख 23 हजार रूपये) कमाती हैं। यह कम्पनी अमेरिका की है।

युद्ध में काम आने वाली मिसाइलें को बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी सेस्त्र एयर क्राफ्ट (Cesna Aircraft) है। अपने स्थापित होने से सन् 1994 तक यह कम्पनी 17 लाख 81 हजार मिलाइलें बनाकर दुनिया के विभिन्न देशों को बेच चुकी हैं। यह कम्पनी सन् 1911 में स्थापित हुयी थी। सामान्य रूप से यह कम्पनी प्रति वर्ष लगभग 2,300 मिसाइलें का उत्पादन करती है। युद्ध के दिनों में कम्पनी का उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि मिसाइलों का उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि मिसाइलों की खपत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिये ईरान–ईराक युद्ध के समय में कम्पनी ने 3000 मिसाइलों का उत्पादन प्रतिवर्ष किया था। यह अमेरिकी कम्पनी है।

विश्व भर में जितनी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनीयाँ हैं उनमें सबसे बड़ी है – हथियारों का उत्पादन करने वाली अमेरिका बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'जनरल मोटर्स' (General Motors)। इस कम्पनी ने सन् 1994 में 154 अरब डालर (4928 अरब रूपये) की बिक्री की अपने उत्पादों को बेचकर।

दुनिया में सबसे अधिक विषैली गैसों का उत्पादन करने वाली कम्पनी अमेरिकी की है जिसका नाम है 'ड्यूपान्ट' (Dupont) दुनिया के सभी विकासशील देशों में उत्पादन के तौर तरीकों के कारण जितनी विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, उस मात्रा का 10 गुना अधिक, विषैली गैसें अकेले ड्यूपान्ट उत्पादित करती है। ध्यान रहे कि, ये विषैली गैसें ओजोन की परत को लगातार कमजोर करने के लिये जिम्मेदार हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण के विनाश के लिये अगर सबसे अधिक जिम्मेदार कोई है, तो वह है–अमरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'ड्यूपान्ट' (Dupont) दूसरे स्थान पर आती है ब्रिटेन की 'इम्पीरियल केमीकल इन्डस्ट्री' (I.C.I.) दोनों कम्पनियों के दुनिया भर में स्थित कारखाने, 500 टन के बराबर प्रतिदिन जहरीली गैसें छोड़ते हैं।

सबसे अधिक लडाकू विमानों का उत्पादन करने वाली कम्पनी हैं – 'बोइंग'। इस कम्पनी ने सन् 1994 में लगभग 21 अरग डालर (672 अरब रूपये) के लड़ाकू विमान बनाये। यह अमरिकी कम्पनी अन्य मालवाहक व यात्री वाहक हवाई जहाज भी बनाती है।

दुनिया में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कम्पनी 'इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन' (I.B.M.) अमेरिका की है। इस कम्पनी का सन् 1994 का विशुद्ध मुनाफा लगभग 58 अरब डालर (1856 अरब रूपये) था। यह कम्पनी इलैक्ट्रानिकी की चीजें बनाने के अलावा हथियार भी बनाती है।

दुनिया में सबसे अधिक शराब का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'एनह्यूसर–बुश इनकार्पोरेशन (Anheuser-Bush Incorporation) अमेरिका की है। यह कम्पनी विश्व के 54 देशों में बेचने के लिये 92 अरब 13 करोड़ लीटर शराब प्रति वर्ष बनाती है।

दुनिया में सबसे अधिक सिगरेटों का उत्पादन करके बेचने वाली कम्पनी अमेरिका की 'आर.जे. रेनाल्ड टोबैको कम्पनी' है। यह कम्पनी प्रति वर्ष 110 बिलियन (110 अरब) सिगरेटों का उत्पादन करती

है। याद रहे कि 500 सिगरेटों के बनाने में एक बड़ा पेड़ समाप्त हो जाता है। पूरे विश्व में लगातार पेड़ों की संख्या अत्यन्त तेजी से कम होती जा रही है।

विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापन बनाने वाली कम्पनी 'सात्ची एण्ड सात्ची' (Satchi And Satchi) ब्रिटेन की है। कम्पनी ने दुनिया की तमाम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये सन् 1988 में 135 अरब 29 करोड़ डालर (257 अरब 5 करोड़ रूपये) के विज्ञापन तैयार किये थे।

प्रतिवर्ष विज्ञापन पर सबसे अधिक खर्चा करने वाली कम्पनी 'सीयर्स रोब्यूक एण्ड कम्पनी' (Sears Roebuk And Company) अमेरिका की है। सन् 1988 में इस कम्पनी ने 1 अरब 18 करोड़ 68 लाख डालर 822 अरब 54 करोड़ 92 लाख रूपये) विज्ञापन पर खर्च किये। यह कम्पनी रेडीमेड वस्त्र तथा जुतों का उत्पादन करती है।

विश्व की 570 ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं जिनमें प्रत्येक का वार्षिक कारोबार 20 अरब डालर (640 अरब रूपये) से भी अधिक है। इनमें सबसे विशालकाय 100 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा है।

दुनिया में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सबसे बड़ा समूह "जैसपर ग्रुप" (Jespar Group) है, जिसके पास अकेले अपनी 451 बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं।

जुलाई 1995 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 12,32,951 कम्पनियाँ हैं। इनमें 102664 सरकारी तथा बाकी निजी कम्पनियाँ है।

पश्चिमी जर्मनी व यूरोप के कई अन्य देशों में चल रहे 'ग्रीन पीस मूवमेंट' की अक्टूबर 1994 की रिपोर्ट में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – "ऐसी कोई भी कम्पनी जो एक साथ दुनिया के एक से अधिक देशों में काम करती हो, बहुराष्ट्रीय कम्पनी मानी जानी चाहिए।"